भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2005

सं0 310–3(1)/2003–इको.– भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) तथा धारा 11 (i) (बी) (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता हैः

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**

(i) इस आदेश का नाम "दूरसंचार टैरिफ (चौंतीसवां संशोधन) आदेश, 2005" (2005 का 1) होगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची IV का वर्तमान शीर्ष हटा दिया गया और इसके स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा।

<u>अनुसूची IV</u>

<u>घरेलू लीज्ड सर्किट्स</u>

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में अनुसूची IX के बाद निम्नलिखित नई अनुसूची जोड़ी जाएगी :

अनुसूची X

अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (आईपीएलसी)–(हॉफ सर्किट)

	मद	टैरिफ
(1)	कार्यान्वित किए जाने की तारीख	1.4.2005
(2)	कवरेज	(क) सभी टैरिफ अधिकतम सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट (ख) टैरिफ की निर्धारित अधिकतम सीमा सभी गंतव्यों, क्षमताओं तथा वॉयस अथवा डाटा के वहन के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी किस्म की केबल प्रणालियों पर लागू होगा। (ग) सेवा प्रदाता टैरिफ की अधिकतम सीमा में रियायत प्रदान कर सकते हैं। रियायत, यदि प्रस्ताव किया जाता है, तो पारदर्शी, निर्धारित मानदण्ड पर आधारित गैर–भेदभावपूर्ण होनी चाहिए और इसे ट्राई को सूचित किया जाना चाहिए। (घ) अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे सभी रूटों/गंतव्यों के लिए हॉफ सर्किट का भी प्रस्ताव करें जिनके लिए पूर्ण सर्किटों का प्रस्ताव किया जाता है।
(3)	आईपीएलसी के लिए टैरिफ	(see table below)

क्षमता/गति	प्रतिवर्ष टैरिफ की अधिकतम सीमा (रुपए लाख में)
ई–1	13
डीएस–3	104

		एसटीएम–1	299
(4)	**ई–1 से कम क्षमता/गति के लिए टैरिफ**	प्रविरिति	
(5)	**सैटेलाइट मीडिया के माध्यम से आईपीएलसी के लिए टैरिफ**	प्रविरिति	
(6)	**आईपीएलसी से संबद्ध सभी अन्य मामले**	प्रविरिति	

सामान्य

इस आदेश के किसी प्रावधान के संबंध में संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुबंध–क में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में संशोधन करने का कारण स्पष्ट किया गया है।

आदेशानुसार

(डॉ0 हर्षवर्धन सिंह)

सचिव एवं प्रधान सलाहकार

अनुबंध–क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट–हॉफ सर्किट (जिसे इसके पश्चात् यहां आईपीएलसी कहा जाएगा) एक समर्पित प्वाइंट–टू–प्वाइंट कनैक्शन है, जिसमें दो प्वाइंटों, जिसका एक प्वाइंट भारत में तथा दूसरा प्वाइंट विदेश में हो, के बीच, नॉन–स्विच्ड, फिक्सड तथा सुनिश्चित बैंडविड्थ मुहैया की गई होती है। मोटे तौर पर कहा जाए तो आईपीएलसी दूर (Far End) तथा नजदीक (Near End) में विभाजित होता है जिसे हॉफ सर्किट कहा जाता है। दूर (Far End) का टैरिफ विदेशी वाहक तथा उसके भारतीय समकक्ष के बीच की आपसी वार्ता सहित कई कारकों पर निर्भर करता है।

2. अभी तक टीटीओ, 1999 में आईपीएलसी के लिए टैरिफ में प्रविरिति रखी गई थी। सॉफ्टवेयर निर्यातक, बीपीओ यूनिट, बैंक तथा अन्य वित्तीय सेवा कंपनियां तथा इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपीएस) और आईएलडीओएस, आईपीएलसीएस के महत्वपूर्ण उपयोगकर्ता थे। आईपीएलसी, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा (आईटीईएस) उद्योगों जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के लिए एक बुनियादी आवश्यकता समझी जाती है। दुनिया में भारत आईटीईएस का एक अग्रणी प्रदाता बन कर उभरा है और यह इस सेक्टर में तेजी से अपना जोरदार स्थान बना रहा है। इसके अलावा, आईएसपीएस विदेश में अपने अपस्ट्रीम कनेक्टिीविटी के लिए भी आईपीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। यदि बाजार प्रतिस्पर्धी न हो तो इन महत्वपूर्ण साधनों की लागत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर आधारित होने चाहिए। ब्राडबैंड को बढ़ावा देना सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया है जिसे उदाहरण के लिए सरकार की ब्राडबैंड नीति 2004 से देखा जा सकता है जिसमें बुनियादी रूप से ग्रामीण भारत में सामाजिक–आर्थिक अवसरों के परिवर्तन का आधार दिया गया है। उपभोक्ता कीमतें वहनीय होना जरूरी है।

3. प्राधिकरण को उपयोगकर्ता समूहों जैसे कि नैस्सकॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसो0 ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई), कॉल सेन्टर्स एसो0 ऑफ इंडिया तथा अन्य बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) यूनिटों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें इस आधार पर कि

आईपीएलसी के लिए भारत में टैरिफ कई देशों से बहुत ज्यादा हैं, जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिनके साथ भारतीय उद्यमियों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा आईटीईएस सेक्टर से संबंधित विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी होती है, आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित करने का अनुरोध किया गया था।

4. इस संबंध में, प्राधिकरण ने उपयोगकर्ता समूहों, सेवा प्रदाताओं आदि के साथ बैठकें की। वर्तमान तथा संभावित प्रमुख निवेशकों की राय थी कि भारत में बैंडविथ की ऊंची कीमत सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में निवेश आधार बढ़ाने में एक वाधक कारक है और भारत इस प्रकार वैकल्पिक गंतव्यों की तुलना में निवेश में हानि उठा रहा है। 25.7.03 से 4.2.04 की अवधि के दौरान प्राधिकरण ने वीएसएनएल (VSNL) तथा दूसरे आईएलडीओएस के साथ अकेले आईपीएलसी के टैरिफ के मुद्दे पर कई बैठकें की। ये बैठकें केबल स्टेशन सुविधाओं के अभिगम (Access) से संबंधित मुद्दों पर वीएसएनएल (VSNL) तथा रिलायंस के साथ की गई बैठकों के अतिरिक्त थीं। इन बैठकों में सेवा प्रदाताओं (आईपीएलसी) ने प्राधिकरण को आश्वासन दिया कि आईपीएलसी (ऑफ सर्किट) के लिए लीज किराया लगभग छह माह की अवधि में काफी कम हो जाएंगे।

5. प्राधिकरण ने भी देश में ब्राडबैंड/इंटरनेट सेवाओं के विकास के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण किया और देखा कि भारत में बैंडविथ की कीमतें ऐसे धनी देशों, जिन्होंने अपने ब्राडबैंड के विस्तार के संबंध में अच्छा कार्य किया है, से काफी ज्यादा हैं। प्राधिकरण ने इस बात को भी समझा कि पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में मोबाइल सेक्टर के असाधारण विस्तार में कीमतों की कमी ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ–साथ इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि सामान्य तौर पर देश में ब्राडबैंड तथा इंटरनेट सेवाओं की व्यवस्था करने की लागत का एक बड़ा भाग बैंडविथ की लागत है। इंटरनेट तथा ब्राडबैंड पेनेट्रेशन के त्वरित विकास के संबंध में ब्राडबैंड इंडिया की सिफारिशों में कहा गया है कि (अध्याय 4 में पैरा 4.1.2 देखें) घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय दोनों खातों में बैंडविथ की लागत कुल मासिक लागत का 45% से ज्यादा है और यह इससे भी ज्यादा हो सकता है यदि कम कीमत तथा सेवा की उच्चतर गुणवत्ता की इच्छा की जाए।

इस प्रकार, देश में ब्राडबैंड पेनेट्रेशन की उच्चतर दर प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत पर आईपीएलसी सेवा प्रदान करना एक बुनियादी आवश्यकता है।

6. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण ने आईपीएलसी के टैरिफ तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा की सीमा की जांच करने का निर्णय लिया। आईपीएलसी की कीमतों की अपनी समीक्षा के भाग के रूप में प्राधिकरण ने बाजार में मौजूद कीमतों की जांच की और नोट किया कि आईपीएलसी के लीज किराए आशा के अनुरूप कम नहीं हुए और वे अन्य देशों के किरायों की तुलना में काफी ज्यादा थे (देखें अनुबंध क के परिशिष्ट 1 में तालिका 1 से 3 तथा 5 से 7)

7. इन पहलुओं को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने 30 अप्रैल, 2004 को आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श–पत्र में दिया गया लागत आधारित कीमत, वीएसएनएल (VSNL) द्वारा प्रस्तुत की गई कीमत पर आधारित था और उन्हें आईपीएलसी की लागत पर आधारित टैरिफ की अधिकतम सीमा की और गहन जांच करने का प्रारंभिक बिन्दु के रूप में देखा गया। विभिन्न हितधारियों, जिसमें सेवा प्रदाता, उपयोगकर्ता उद्योग, उपभोक्ता संगठन और सेवा प्रदाताओं की एसोशिएशन शामिल थे, ने इस परामर्श–पत्र पर अपनी लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की। इस संबंध में दिल्ली तथा बैंगलोर में क्रमशः 20.7.04 तथा 22.07.04 को ओपन हाऊस विचार विमर्श भी किए गए।

8. आईपीएलसी के संबंध में इस परामर्श के साथ–साथ प्राधिकरण ऑपरेटरों से पृथक लेखा प्राप्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहा ताकि सेवा प्रदाताओं द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए समुचित रूप से आवंटित लागत ट्राई को उपलब्ध हो। प्राधिकरण को वीएसएलएल (VSNL) के पृथक लेखा 31 दिसम्बर, 2004 को प्राप्त हुए। इन आंकड़ों पर भी आईपीएलसी टैरिफ के निर्धारण के संदर्भ में ट्राई ने विचार किया।

खण्ड II

मुख्य टिप्पणियों का सार

9. परामर्श पत्र पर हितधारियों की विभिन्न टिप्पणियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

(क) क्या आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) को आगे विनियमित किया जाना चाहिए?

- उपयोगकर्ता समूह और उपभोक्ता संगठनों की राय थी कि जब तक बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं हो जाती तब तक आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित किए जाए।

- सामान्य तौर पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने इस बात पर अपनी चिन्ता व्यक्त की कि 2002 में आईएलडी सेक्टर की शुरूआत हो जाने के बावजूद आईपीएलसी के कारोबार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं आई है और इसलिए उनकी राय थी कि प्राधिकरण को न केवल आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित करने चाहिए बल्कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए भी और कदम उठाने चाहिए।

- बहुत से हितधारियों द्वारा इस समय आईपीएलसी के टैरिफ विनियमित करने के लिए ट्राई का हस्तक्षेप इस आधार पर आवश्यक समझा क्योंकि लागत पर आधारित कीमतों पर आईपीएलसी की उपलब्धता से इंटरनेट तथा ब्राडबैंड सेवाओं का विकास होगा और उनकी पैठ बढ़ेगी।

- परामर्श पत्र पर अपनी प्रस्तुति में एक सेवा प्रदाता ने कहा कि ट्राई द्वारा आईपीएलसी के टैरिफ का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जिनसे भारत में आईपीएलसी की कीमतें अधिक वहनीय बनें और ये एशिया–पैस्फिक क्षेत्र में मौजूद बाजार की कीमतों के अनुरूप हों।

- एक राय यह थी कि इंटरनेट के उपयोग के उद्दीपन तथा उसे बढ़ावा देना और वहनीय ब्राडबैंड सेवाओं की उपलब्धता अन्य बातों के साथ–साथ कम

कीमत की इंटरनेशनल बैंडविथ की अभिगम्यता पर निर्भर करता है क्योंकि आईपीएलसीएस इन सेवाओं के लिए मुख्य अन्तरराष्ट्रीय वाहक प्लेटफार्म है।

- एक राय यह भी व्यक्त की गई कि भारत में आईपीएलसी की उंची कीमतें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय डाटा राजस्व की संभावित विकास के मार्ग में बाधक है और इससे क्षमता की कम मांग का अनुमान भी लगता है। इस प्रकार, आईपीएलसी की उंची कीमतें, उपभोक्ता सेवाओं की मांग भी प्रभावित करती हैं जो अन्यथा बड़े पैमाने पर बैंडविथ क्षमता की व्यवस्था करते।

- जब तक आईपीएलसी की कीमतों को कम नहीं किया जाता तब तक बीपीओ सेवाओं के ग्राहक बड़े पैमाने पर उन देशों की ओर मुड़ेंगे जो कम कीमत पर बीपीओ सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करेंगे। इसका भारत में बीपीओ उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- ट्राई को टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए ताकि वीएसएनएल (VSNL) की दरें लागत आधारित हों। समय–समय पर टैरिफ की समीक्षा की जानी चाहिए परन्तु जब तक यह न समझा जाए कि बाजार की प्रभावी शक्तियां आईपीएलसी की दरों पर पर्याप्त दबाव डाल सकती हैं तब तक इसे बनाया रखा जाना चाहिए।

- एक आईएलडीओ की टिप्पणी थी कि कीमत, बाजार की मांग तथा सप्लाई पर निर्भर करता है इसलिए बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। परन्तु विनियामक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे ऑपरेटर जिनके पास काफी क्षमता हो (Bottleneck सुविधाएं) वे बैंडविथ सप्लाई प्रतिबंधित न करें और इस प्रकार कृत्रिम रूप से कीमतों को न बढ़ाए। तदनुसार, विनियामक को Bottleneck सुविधाओं जैसे कि महत्वपूर्ण ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले लैडिंग स्टेशनों, की आसान अभिगम्यता सुनिश्चित करनी चाहिए।

- इन्कमबेंट की राय की कि बाजार की शक्तियों को कीमत निर्धारित करने देना चाहिए और इस प्रकार आईपीएलसी की कीमतों को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वीएसएनएल (VSNL) की राय थी कि बाजार को विनियामित करने का कोई भी प्रयास निवेश को प्रभावित करेगा और इस प्रकार इससे विकास भी प्रभावित होगा। उनका यह भी मानना था कि इससे ग्राहकों को पैकेजों की पेशकश करने में जटिलता भी आ सकती है।

- इन्कमबेंट का मत था कि सप्लाई बढ़ने से अगले 12–18 महीने में भारत मे आईपीएलसी की कीमतें 30% तक घटने की संभावना है।

- वीएसएनएल (VSNL) ने कहा कि आईटी, आईटीईएस तथा ब्राडबैंड सेवाओं की कीमत संरचना का एक बहुत छोटा भाग ही आईपीएलसी की कीमत से सम्बद्ध है।

(ख) क्या प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कटौती पर्याप्त है, पर्याप्त से कम है या यह बहुत ज्यादा है

- एक आईएलडीओ ने कहा कि ई 1 सर्किट के लिए 12 लाख रुपये की प्रस्तावित टैरिफ की अधिकतम सीमा बहुत ही ज्यादा है। वीएसएनएल (VSNL) के वर्तमान टैरिफ पर 15% से 20% की कटौती अधिक यथार्थ है। इसी प्रकार, डीएस 3 क्षमता के लिए प्रस्तावित किए गए ई 1 की अधिकतम सीमा के 8 गुणा को अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार के आधार पर संशोधित कर ई1 का 11 गुणा किया जाना चाहिए।

- एक दूसरे आईएलडीओ की राय थी कि प्राधिकरण द्वारा टैरिफ में प्रस्तावित कटौती प्रभावकारी है। तथापि, हॉफ सर्किट के टैरिफों को उन देशों की तुलना में जो बीपीओ/आईटीईएस सेक्टर में भारत से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, की तुलना

में अधिक आकर्षक बनाया जाना चाहिए। ऐसा कारोबार करने का आर्कषक वातावरण मुहैया करने के लिए नितान्त आवश्यक है।

- टेलीकॉम सेक्टर के एक स्टैंड अलोन प्लेयर ने यह राय व्यक्त की कि यद्यपि विभिन्न सर्किटों की कीमतों का आकलन करने के लिए लागत+पद्धति अपनाई जा सकती है, परन्तु इसे अन्तरराष्ट्रीय कीमतों के लिए बेंचमार्क माना जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एकाधिकार प्राप्त सेवा प्रदाता वीएसएनएल (VSNL) को उसकी अकुशलता से लाभ प्राप्त न हो।

- आईएसपीएआई की राय थी कि परामर्श पत्र में प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव की गई कटौती बहुत कम है और यह बहुत विलम्ब से की गई है। यह कटौती यह देखते हुए भी बहुत कम है कि आईएसडी टैरिफ में तेजी से आई कमी के लाभ को आईएलडीओएस ने जानबूझकर आईपीएलसी के उपयोगकर्ताओं को प्रदान नहीं किया।

- सीओएआई ने अपनी लिखित टिप्पणी में कहा कि प्राधिकरण द्वारा अपने परामर्श पत्र में प्रस्तावित कटौती बहुत कम है और यह बहुत विलम्ब से की गयी है। यह कटौती यह देखते हुए भी बहुत कम है कि आईएसडी टैरिफ में तेजी से आई कमी के लाभ को आईएलडीओएस ने जानबूझकर आईपीएलसी के उपयोगकर्ताओं को प्रदान नहीं किया।

- एक आईएसपी ने टिप्पणी की कि वीएसएनएल (VSNL) की आईपीएलसी टैरिफ का प्रारंभिक निर्धारण करते समय इसी प्रकार के आईपीएलसी क्षमताओं के लिए एशिया–पैस्फिक क्षेत्र में अन्यत्र प्रभारित की जाने वाली बाजार दरों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।

(ग) पद्धति तथा संबंधित मुद्दे, कीमत–मल्टीपल सहित

- एक आईएलडीओ की राय थी कि टैरिफ के निर्धारण के लिए प्राधिकरण का लागत आधारित दृष्टिकोण उचित प्रतीत होता है, परन्तु कुछ स्थानों पर अनुमान ज्यादा लगाए गए हैं।

- आईएसपीएआई की टिप्पणी यह थी कि अधिकांश अन्तरराष्ट्रीय केबल कई देशों से गुजरते हैं इसलिए निवेश संबंधी निर्णय भारत जैसे एक देश की संभावनाओं तथा वर्तमान बाजार पर आधारित नहीं होता है। लागत के आकलन के लिए यह पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है।

- सीओएआई ने टिप्पणी की कि आईएलडी की समस्त लागत केवल आईपीएलसी पर डालना अनुचित है।

- एक विदेशी वाहक ने कहा कि ट्राई, प्रारंभिक चरण में प्रस्तावित दर कटौती को अपनाए परन्तु बाद में पद्धति की पूरी एलआरआईसी का अध्ययन किया जाना चाहिए।

- एक दूरसंचार सेवा प्रदाता ने कहा कि पद्धति उचित प्रतीत होती है, परन्तु यह समझा जाना चाहिए कि संस्थापित क्षमता काफी अधिक है। नाममात्र की क्षमता का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि संस्थापित क्षमता उपलब्ध की जाए तो प्रति ई 1 लागत काफी कम होगी। यह उल्लेखनीय है कि मांग है और जैसे ही क्षमता उपलब्ध होती है, बाजार उसे समाहित कर लेता है।

- वीएसएनएल (VSNL) ने यह टिप्पणी की कि पत्र में यह माना गया है कि कुल उपलब्ध केबल क्षमता पहले दिन ही बेच दी जाएगी और यह अगले 15 वर्ष तक बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी और इसमें कोई रिक्ति या अनिरन्तरता नहीं होगा। यह तथ्य से काफी दूर है। व्यवहार में यह मानना सही नहीं है कि अगले 15 वर्षों में कीमतों में कोई कमी नहीं होगी। यह मानना भी सही नहीं है

कि Entity की संपूर्ण परिचालनिक लागत वसूल करने के लिए 10% का परिचालिक व्यय पर्याप्त है। इस पद्धति में परिसम्पत्ति की वास्तविक कार्यकाल (Life) तथा और आर्थिक कार्यकाल के बीच अन्तर नहीं किया गया है।

- वीएसएलएल (VSNL) ने परामर्श–पत्र में निहित पद्धति में मानी गई कुछ बातों पर भी टिप्पणी की। इनमें ट्राई द्वारा मानी गई कुल लागत में सैटेलाइट लागत का भाग पूंजीगत लागत के अनुमान के अंतर्गत ज्यादा मानना तथा पूंजीगत लागत का कम अनुमान तथा पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक प्रभारों की व्यवस्था के लिए कम प्रावधान मानना शामिल है।

- वीएसएनएल (VSNL) ने यह भी टिप्पणी की कि यद्यपि प्राधिकरण ने एनएलडी कीमत निर्धारण के लिए 1:21:63 का अनुपात अनुमोदित किया है, परन्तु आईपीएलसी के कीमत निर्धारण के लिए इसने 1:8:23 का ही प्रस्ताव किया है। बहरहाल दोनों सेवाओं में एक ही किस्म की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इनमें मल्टीप्लेक्सिंग/डिमल्टीपलेक्सिंग की संबद्ध लागत भी समान अनुपात में होती है।

- एक दूसरे आईएलडी ने यह उल्लेख किया कि वे इस पद्धति से सहमत है कि एक ई 1 को बैंडविथ के उच्चतर मल्टीपल के लिए बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया सकता है। तथापि, ई 1 की लागत तथा ओएण्डएम प्रभार तथा इसकी उच्चतर क्षमताओं में कोई रेखीय (Linear) संबंध नहीं होता है। अतः बैंडविथ मल्टीपल को लागत मल्टीपल के रूप मानना उचित नहीं है। लागत मल्टीपल के लिए अन्तरराष्ट्रीय मानक भारत के मानक से भिन्न हो सकते हैं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। अतः उन्होंने सिफारिश की कि विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय अनुपात स्वीकार किया जाना चाहिए।

- नैसकॉम के विचार में अपनाई गई पद्धति से अनुपात सही दिशा में बन रहा है और यह एक अच्छी शुरूआत है। परन्तु जब डी–एस–3 तथा एसटीएम–1 का उपयोग बढ़ेगा, तब समान बेंचमार्क तथा मौजूदा मल्टीपल वैध नहीं रहेंगे और इनकी समय–समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। उस समय ट्राई को उपयोग कारक, सेवाओं की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता और संकुलन के स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।

- निवेश का विश्लेषण करने वाली एक फर्म ने यह टिप्पणी की कि वे लागत मूल्य में ट्राई द्वारा निर्दिष्ट कीमत–मल्टीपल से सहमत हैं क्योंकि इनका युक्तिसंगत आधार है और ये दूसरे देशों में तदनरूपी मल्टीपल के अनुरूप भी हैं।

- एक दूरसंचार सेवा प्रदाता ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के तेजी से बदलते हुए डायनेमिक्स को देखते हुए जो भी टैरिफ ट्राई निर्धारित करेगी उसकी 12 माह बाद समीक्षा की जानी चाहिए।

- अधिसूचित अधिकतम सीमा की नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। यह जांच वर्ष में कम से कम दो बार होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो अधिकतम सीमा संशोधित की जानी चाहिए। बहरहाल, यदि वर्ष में एक बार "रिटेल माइनस" कीमत शुरू कर दी जाती है तो तब आपवदिक स्थिति में हस्तक्षेप करने के अलावा, समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है।

- इस मुद्दे पर कि चाहे अंतिम उपयोग (End use) वॉयस अथवा डाटा कुछ भी क्यों न हो क्या समान टैरिफ लागू किया जाना चाहिए अधिकांश स्टेकहोल्डरों की राय थी कि डाटा अथवा वॉयस के लिए आईपीएलसी मुहैया कराने की लागत में कोई अन्तर नहीं होता है और यदि अन्तर होता भी है तो यह बहुत ही कम होता है। अतः सम्बद्ध आईपीएलसी के लिए कोई लागत आधारित औचित्य नहीं है। भारतीय व्यापार तथा उपभोक्ताओं दोनों को कम कीमत पर

सामान्यतः पीसीटीएन आधारित अन्तरराष्ट्रीय वॉयस सेवाओं के विस्तार तथा उच्चतर गुणवत्ता मानकों का लाभ मिलेगा।

- उद्योग के एक एसोशिएशन ने कहा कि आईएलडीओएस लाइसेंस की शर्तों के अनुसार Bottleneck सुविधाएं सभी उपयोगकर्ताओं तथा दूसरे आईएलडीओएस को देने के लिए वचनबद्ध हैं। इस समय केबल क्षमता एक कठिनाई है क्योंकि भारत में सीमित लैंडिंग स्टेशन हैं। आईएलडीओएस, खासतौर पर ऐसे आईएलडीओएस, जिनके पास "इन्कमबेंट" सुविधाएं हैं, को दूसरे आईएलडीओएस को रियायती दरों पर पेशकश करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि क्षमता की उच्चतर आवश्यकता प्रतिबिम्बित हो और इस Bottleneck सुविधा की भागीदारी को भी बढ़ावा मिले।

- इन्कमबेंट ने कहा कि उन्होंने विगत में उस समय आधारभूत संरचना पर निवेश किया जब देश को इसकी आवश्यकता थी और जब कीमतें बहुत ज्यादा थी। जब ये अपने प्रतिस्पर्धियों को आईपीएलसी सेवाओं की पेशकश करें तो उन्हें अपने नेटवर्क की कम्पोजिट लागत की भरपाई करनी होगी। एसे प्रतिस्पर्धियों (आईएलडीओएस) जो सेवाओं की बिक्री करते हैं, के टैरिफ, उन कार्पोरेट ग्राहकों, जो सेवाओं की बिक्री नहीं करते हैं, के टैरिफ से भिन्न रखने की आवश्यकता है।

(घ) अन्य टिप्पणियां

- लम्बी अवधि में क्षमता वृद्धि सहित लागत के सभी तत्वों के लागत के आधार पर फारवर्ड लुकिंग दीर्घकालिक वर्द्धमान लागत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए नेटवर्क संबंधी अर्थशास्त्र की गहरी समझ अपेक्षित है। मॉडल अनुमान विषयनिष्ठ होते हैं।

- एलआरआईसी सेवा अर्थशास्त्र को सही–सही प्रकार से प्रतिबिम्बित करता है और यह अकुशल इन्कमबेंट की रक्षा नहीं करता है।

- जहां बैंडविथ की मांग रहती है उन रूटों पर कम कीमत देखे जाते हैं और सप्लाई प्रचुर हो जाती है।

- विभिन्न मार्केटों में मौजूद क्षमता के परिणामस्वरूप 'हब' (जैसे कि हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम) तथा "स्पोक्स" (जैसे कि थाइलैंड, इंडोनेशिया, ब्राजील) बनते हैं। हब से स्पोक के अथवा एक स्पोक से दूसरे स्पोक की तुलना में एक हब से दूसरे हब की कीमतें कम होती हैं।

- रूटों के अनुसार कीमतें अलग–अलग होती हैं।

- परामर्श–पत्र में अपनाई गई पद्धति सही नहीं है क्योंकि इसमें 28% की पूंजी वसूली तथा 18 वर्ष की परिसंपत्ति का कार्यकाल लिया गया है।

- मौजूदा लागत तथा वर्द्धमान दोनों के हिसाब से स्वामित्व वाली तथा कंसोर्टियम केबल की लागत अलग–अलग होती है।

- कसोर्टियम केबल की कीमतों में परिवर्तन की बहुत कम लोचशीलता होती है।

- वर्द्धमान कीमतों से तुलना करना सही नहीं है क्योंकि ये कीमतें दिवालियापन तथा परिसंपत्तियों की सूचीबद्ध कीमतें प्रतिबिम्बित करती हैं।

खण्ड III

बेंचमार्क के साथ भारतीय आईपीएलसी टैरिफ की तुलना

1) सूचीबद्ध कीमतों से तुलना

10. आईपीएलसीएस के लिए भारत में मौजूद टैरिफों की तुलना अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क और वीएसएनएल (VSNL) के पृथक लेखों में उपलब्ध लागत के आंकड़ों का इस्तेमाल करके निकाले गए लागत आधारित अनुमान से की गई।

11. घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श करके प्राधिकरण ने बैंडविथ के लिए अन्तरराष्ट्रीय लीज कीमतों के विभिन्न पहलुओं, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क का कार्य, सब–मेरीन नेटवर्क के लिए केबल बिछाने की लागत के रूझान, उन विभिन्न देशों में जहां कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं, बाजार की संरचना, आईपीएलसी सेक्टर को शासित करने वाला विनियामक वातावरण आदि भी शामिल है, की जांच की।

12. विभिन्न कारकों से पिछले पांच से ज्यादा वर्षों से बैंडविथ के अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपस्फीति रही है। बैंडविथ के अन्तरराष्ट्रीय बाजार में 1990 के दशक में ज्यादातर समय 2Mbps अर्थात् E1 सर्किट ने क्षमता खरीद के मामले में प्रमुख यूनिट के रूप में कार्य किया। धीरे–धीरे D3-3S (डिजीटल सिगनल 3) अथवा एसटीएम–1 (सिन्क्रोनस ट्रांसफर मोड्यूल–1) न्यूनतम खरीद विकल्प बन रहे हैं। पूरे क्षेत्र में कीमतों के रूझान की तुलना के प्रयोजन के लिए अब एसटीएम–1 लीज कीमत, ज्यादातर प्रयोग किया जाने वाला डिनोमिनेटर है। आगे, पूरे क्षेत्र में एसटीएम–1 के लीज कीमतों के रूझानों की तुलना की गई है।

13. यह पाया गया है कि ट्रांस–अटलांटिक क्षेत्र में एसटीएम–1 की कीमतों का माध्य 2000 में 70%, 2001 में 65%, 2002 तथा 2003 प्रत्येक में 26% और 2004 में 25% कम हुआ। ट्रांस पैस्फिक क्षेत्र में एक प्रतिनिधिक रूट पर एसटीएम–1 की कीमतों का माध्य

2003 में 56% तथा 2002 में 40% गिरा। यूरोप–एशिया क्षेत्र में एसटीएम–1 सर्किट की कीमतों का माध्य 2003 में लगभग 42% गिरा जो पिछले वर्ष आई गिरावट के समान है। एशिया में एसटीएम–1 लीज कीमतों का माध्य 2003 में 50% से 60% गिरा (स्रोतः प्रीमेट्रिका, आईएनसी, 2004 वाल 1:सबमेरीन नेटवर्क)। इस पृष्ठभूमि की तुलना में 2002 से 2005 की अवधि के दौरान भारत से प्रारंभ होने वाले एसटीएम–1 (भारत से अमेरिका के लिए) की लीज कीमत में संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के हिसाब से केवल लगभग 10% कम हुई। भारत से प्रारंभ होने वाले (भारत से अमेरिका के लिए) DS 3 और E 1 क्षमताओं के लीज कीमत में तदनरूपी प्रतिशत गिरावट क्रमशः 8% और 10% है।

14. उपर्युक्त की भारतीय कीमतों से तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में, सेवाओं की अन्तरराष्ट्रीय क्षमता की लीज कीमत की गिरावट की सीमा दुनिया के दूसरे भागों की गिरावट की सीमा से काफी कम है।

15. आईपीएलसी सेवा प्रदान करने की लागत के रूझानों की समीक्षा भी की गई थी और यह पाया गया कि मुख्यतः प्रौद्योगिकी की उन्नति तथा इक्यूमेंट सप्लायर के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण केबल निर्माण तथा सबमेरीन नेटवर्क के अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के लागत में भारी कमी आई है। उदाहरण के लिए बाजार की प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए केबलों का अपग्रेडिंग एक लागत प्रभावी तरीका है। प्रौद्योगिकी की उन्नति, जैसे कि नई मोड्येलेशन तकनीक आदि से पुराने केबल उनके प्रारंभिक अभिकल्पित क्षमता से आगे भी काम करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इस प्रकार केबल प्रणली में अपग्रेशन महत्वपूर्ण पहलू हैं क्योंकि इनसे ऑपरेटर नए केबल के निर्माण करने के बजाय बहुत ही कम लागत पर क्षमता जोड़ लेते हैं। यह इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2003 में सबमेरीन केबल के निर्माण की लागत 1 बिलियन अमेरीकी डालर से कुछ ज्यादा थी जबकि 2001 में यह 12 बिलियन अमेरीकी डालर था (स्रोत प्रीमेट्रीका आईएनसी 2004 वाल 1: सबमेरीन नेटवर्क)। यह न केवल बैंडविथ के लीज कीमतों से प्रतिबिम्बित होता है बल्कि यह अन्तरराष्ट्रीय बाजार में आईआरयू कीमतों से भी प्रतिबिम्बित होता है। (उपयोग का अलोप्य अधिकार)

(ii) वास्तविक कीमतों अर्थात् रियायतों के लिए संशोधित सूचीबद्ध कीमत से तुलना

16. प्राधिकरण ने दूसरे देशों की बाजार कीमतों (आईपीएलसी लीज किराया) की तुलना भारत की आईपीएलसी हॉफ सर्किट के टैरिफों से करना आवश्यक समझा। इस प्रकार की सूचना के स्रोत का पता लगाना बहुत कठिन होता है। सामान्यतौर पर केबल सूचीबद्ध कीमत ही उपलब्ध होते हैं, जो प्रायः मार्केट की वास्तविक कीमतों में बहुत ज्यादा होते हैं। इस प्रयोजन के लिए, अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से पूरी खोजबीन की गई और बाजार की कीमतों के संबंध में सूचना भी प्राप्त की गई। अनुबंध क–परिशिष्ट–I की तालिका 5,6 और 7 में चुनिंदा एशियन देशों में दिसम्बर, 2004 के दौरान कथित रूप से मौजूद आईपीएलसी लीज किरायों (अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा) की तुलना में दूरस्थ गंतव्यों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत में मौजूद आईपीएलसी के टैरिफों से की गई। अन्तरराष्ट्रीय बेंचमार्क के विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय आईपीएलसी की कीमत तुलनात्मक बाजार की कीमतों, खासतौर पर उच्चतर बैंडविथ सर्किटों की कीमतों से काफी ज्यादा है। अतः एशिया के बहुत से देशों, जिनमें से कुछ देश ग्लोबल बिजनेस प्रासेसिंग ऑपरेशन बिजनेस में भारत के प्रतियोगी हैं, से तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि अन्तरराष्ट्रीय बैंडविथ की भारत में प्रतिस्पर्धी कीमत नहीं है। ये कीमतें ब्राडबैंड की लागत का अभिन्न अंग हैं और इस कठिनाई दूर करने की किसी नीति के संबंध में और भारत में ब्राडबैंड के विकास, खासतौर पर ग्रामीण भारत मे ब्राडबैंड के विकास के लिए इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। लागत और उचित लाभ के आधार पर उपर्युक्त के संदर्भ में कीमतों का विनियमन करना आवश्यक हो जाता है।

17. अतः ऊपर उल्लिखित प्रमाणों से पता चलता है कि भारत में आईपीएलसी के लिए बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण अन्तरराष्ट्रीय बैंचमार्क की तुलना में ज्यादा कीमतें हैं। एक स्वतंत्र परामर्श एजेंसी (गार्टनर, आईएनसी 2004 'मार्केट फोकसःइन्टरनेशनल बैंडविथ प्राइसिंग ट्रैंडस, एशिया–पेस्फिक, 2004) द्वारा हाल की में किए गए एक अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है। एशिया–पेसेफिक में अन्तरराष्ट्रीय बैंडविथ बाजार के संबंध में गार्टनर के अध्ययन का निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

"अन्तरराष्ट्रीय बैंडविथ के लिए सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बाजार हांगकांग, सिंगापुर, जापान, ताइवान तथा दक्षिण कोरिया हैं। सबसे कम प्रतिस्पर्धी बाजार इंडोनेशिया, भारत तथा मलेशिया हैं।"

18. इस संबंध में, दिनांक 30.4.2004 को 'अन्तरराष्ट्रीय निजी लीज्ड सर्किट (हॉफ सर्किट)' पर जारी परामर्श पत्र के पैराग्राफ 5 में प्राधिकरण की निम्नलिखित टिप्पणी उद्धृत करना संगत होगा।

"आईपीएलसी के बिजनेस सेगमेंट में प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं बन पाई है। भारती ही आईपीएलसी का एकमात्र दूसरा प्रदाता है परन्तु इसका परिचालन भी नॉन–रिस्टोरेबल श्रेणी तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त, उनके सबमेरीन केबल रेखीय (Linear) केबल हैं, जिनकी किसी वैकल्पिक केबल की सहायता के बिना अपेक्षित स्तर की उपलब्धता/विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की विश्वसनीयता की आवश्यकता 4 9" की है, जिसे आज मुख्यतः केवल वीएसएनएल (VSNL), जिसके पास मल्टीपल केबल से एक्सेस की सुविधाएं हैं, द्वारा ही मुहैया कराया जा सकता है। विदेश संचार निगत लि0 (VSNL), आईपीएलसी के बिजनेस में मौजूदा ऑपरेटर है और कुछ समय तक बाजार में इसका आधिपत्य रहने की संभावना है।"

19. आईपीएलसी बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी अथवा आईपीएलसी की कीमतें लागत से काफी ज्यादा होने उन ऑपरेटरों के लिए अवसर नहीं रह जाता है जो आईपीएलसी का इस्तेमाल करते हैं परन्तु जिनके पास आईपीएलसी नहीं होती है। यदि अपने सेवा बाजार में उन्हें आईपीएलसी के स्वामित्यों से प्रतिस्पर्धा होती है तो आईपीएलसी के स्वामी उनसे लागत से काफी ज्यादा प्रभार लेते हैं।

खण्ड IV

प्रतिस्पर्धा के मार्ग में बाधक कारक

प्लेयरों की सीमित संख्या

20. भारत में, अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आईएलडी) सेगमेंट 2002 में प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया था। विदेश संचार निगम लि0 (VSNL) एक इन्कमबेंट ऑपरेटर है, जिसके पास मुंबई, कोचीन तथा चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन की सुविधाएं हैं। दूसरे आईएलडीओएस, भारती इन्फोटेल, रिलायंस इन्फोकॉम और डाटा एक्सेस हैं। भारती इन्फोटेल के पास चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन की सुविधा है। भारती इन्फोटेल ने सूचित किया है कि आईपीएलसी में उनका परिचालन केवल 'नॉन–रिस्टोरेबल' श्रेणी तक ही सीमित है। अभी तक रिलायंस इन्फोकॉम ने अपनी केबल लैंडिंग सुविधा की स्थापना नहीं की है। मैसर्स डाटा एक्सेस की अपनी केबल लैडिंग सुविधाएं नहीं हैं। कुछ और समय तक वीएसएनएल (VSNL) के आईपीएलसी बाजार में प्रभुत्व बनाए रखने की संभावना है। इस प्रकार, भारत में आईपीएलसी में मौजूदा बाजार संरचना इस प्रकार की है जिसमें केवल तीन की सक्रिय प्लेयर हैं और उमें केवल दो के पास ही लैंडिंग सुविधाएं हैं। यह देखा गया है कि बहुत से देशों में प्लेयरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और अधिकांश ऑपरेटर गैर–सुविधा आधार वाले ऑपरेटर होते हैं। इस समय भारत में क्षमता की पुनः बिक्री की अनुमति नहीं है क्योंकि अतिरिक्त क्षमता निर्माण पर बल दिया जा रहा है। नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक स्थान में बैंडविथ प्रदाताओं (पुनः बिक्री करने वाले सहित) की संख्या दी गई है :

स्थान	बैंडविथ प्रदाताओं की संख्या
लंदन	33
यूएसए–न्यूयार्क	32
जर्मनी	32
फ्रांस	24
दक्षिण कोरिया	14
भारत	3

स्रोतः एर्नस्ट एण्ड यंग / एनआरए बैवसाइट

सुविधाओं की अभिगम्यता

21. बहुत सी दूरसंचार सेवाओं के लिए सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों की अभिगम्यता को एक आवश्यक साधन माना जाता है। अनावश्यक अभिगम्यता प्रतिबंधों से अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए ऑपरेटर की प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। इस प्रकार, सबमेरीन केबल लैंडिंग स्टेशन दूरसंचार की एक महत्वपूर्ण संरचना है और प्रयास किया जाना चाहिए कि ये दूरसंचार की व्यवस्था के मार्ग में बाधक न बनें। अभिगम्यता के मार्ग की रूकावटों से दूरसंचार ऑपरेटरों की प्रतिस्पर्धा बाधित होती है और यह दूर–संचार बाजार के स्वस्थ विकास के लिए हितकर नहीं है। प्राधिकरण को कई ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें कहा गया कि सुविधाओं की अभिगम्यता में कठिनाई पैदा कर प्रतिस्पर्धा प्रभावित की जा रही है।

22. वीएसएनएल (VSNL) का केबल लैंडिंग स्टेशनों तथा सम्बद्ध सुविधाओं पर नियंत्रण बने रहने से कठिनाई पैदा होती है क्योंकि इन्कमबेंट दूसरे ऑपरेटरों के प्रवेश को रोकता है अथवा इसमें विलम्ब करता है (अथवा कुशल आपरेशन)। अभिगम्यता की समस्या का सामना न केवल आधारभूत केबल ऑपरेटर करते हैं बल्कि यह समस्या उन ऑपरेटरों के सामने भी रहती है, जिन्होंने केबल प्रणाली में क्षमता अर्जित कर ली है परन्तु जो लैंडिंग स्टेशन की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं। उद्योग के साथ वार्ता से पता चलता है कि भारत में केबल लैंडिंग स्टेशन सुविधा की स्थापना करने के लिए न केवल भारी निवेश की आवश्यकता है बल्कि यह एक बहुत समय लगने वाला कार्य भी है, जिसके लिए बहुत सी स्वीकृतियां ली जानी होती हैं, जिसमें सुरक्षा आदि की स्वीकृति भी शामिल है। इस प्रकार केबल लैंडिंग स्टेशनों की अभिगम्यता वास्तव में ऐसे गैर–कीमत कारक हैं जिनका सहारा सप्लायर द्वारा प्रतिस्पर्धा प्रभावित करते हुए लिया जाता है।

23. अतः प्राधिकरण ने नोट किया कि केबल लैंडिंग सुविधाओं के संबंध में प्रतिस्पर्धा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए विनियामक हस्तक्षेप अपेक्षित हैं। बहरहाल, प्रारंभ की गयी परामर्श प्रक्रिया, आईपीएलसी के टैरिफों की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने तक सीमित है और बाजार में प्रोत्साहन बढ़ाने से संबंधित शेष मुद्दों पर विचार, बाद में अलग से परामर्श–पत्र जारी करके किया जाएगा।

खण्ड V

आईपीएलसी विनियमन शासित करने वाले अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार

24. प्राधिकरण ने आईपीएलसी सेगमेंट के विनियमन में अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहारों की समीक्षा की। प्राधिकरण ने इस संबंध में अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से परामर्श किया जिन्होंने आईपीएलसी के लिए संगत विभिन्न दूरसंचार क्षेत्राधिकार संबंधी विनियमों की विस्तृत जांच की (विस्तृत ब्यौरे के लिए अनुबंध–क का परिशिष्ट 1 की तालिका–8 देखें।)

25. अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ प्राधिकरण के परामर्श के दौरान निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष सामने आएः

* उन बाजारों, जिन्हें आज प्रतिस्पर्धी माना जाता है, पर किसी न किसी समय विनियम लागू किए गए थे।

* अब भी कुछ देशों में विनियम, जिसमें टैरिफ संबंधी विनियम शामिल हैं, मौजूद हैं, खासतौर पर प्रभुत्व रखने वाले ऑपरेटर के लिए। बहुत से देशों में जहां आईपीएलसी के लिए कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है वहां भी राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण टैरिफ की समीक्षा/अनुमोदन करता है। (इन्कमबेंट ने भी आंकड़े प्रस्तुत कर इसे माना है। यद्यपि उनका तर्क टैरिफ विनियमित न करने के संबंध में है)

* जब तक बाजार में प्रतिस्पर्धा एक ऐसे स्तर तक नहीं पहुच जाती जहां पर विनियामक सुरक्षित रूप से दृश्यपटल से हट सकता है और प्रतिस्पर्धी शक्तियों को प्रभावी बाजार अनुशासन बनाये रखने की अुनमति दे सकता है तब तक टैरिफ विनियमित किया जाना एक सामान्य प्रक्रिया रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी विनियामक प्राधिकरणों ने भी उनके बाजारों में प्रतिस्पर्धा स्थापित होने से पूर्व इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था।

26. प्राधिकरण ने आईपीएलसी, जिसमें कीमत निर्धारण, इसकी बाजार की संरचना, इस क्षेत्र में अन्यत्र मौजूदा परिस्थितियां और दूसरे क्षेत्रों में आईपीएलसी के विनियम को शासित करने वाले कार्य भी शामिल हैं, के लिए भारत में बाजार की मौजूदा परिस्थितियों, पर विचार किया। इसके अलावा प्राधिकरण ने नोट किया कि आईपीएलसी सेवा प्रदाता आईएसपी सेवा प्रदाता भी हैं और इस प्रकार वे ऐसे दूसरे इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो आईपीएलसी सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बैंडविथ का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार, ये आईपीएलसी प्रदाता (सुविधा आधार वाले आईएलडीओएस) भी अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के टेलीफोनी प्रदान करते हैं। इस सीमा तक गैर–सुविधा आधारित आईएलडीओएस को आईपीएलसी प्रदाताओं की सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रयोजन के लिए भी टैरिफ को लागत आधारित कीमत के रूप में रखने के लिए आईपीएलसी सेक्टर को विनियमित करना प्रासंगिक है। इस उपाय से उद्योग को समान अवसर प्राप्त होगा।

27. उपर्युक्त को देखते हुए और आईपीएलसी के लिए भारतीय बाजार की हाल की और संभावित घटनाओं को देखते हुए प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लागत के आधार पर आईपीएलसी की कीमतों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करने की तत्काल आवश्यकता है। प्राधिकरण इस बात को पूरी तरह मानता है कि अधिकांश विनियामक फारवर्ड लूकिंग लोंग रन इनकरीमेंटल लागत पर विचार करते हुए कीमते निर्धारित करते हैं और यदि हम ऐसी कीमतों में भारी कमी पर विचार करने के बाद इस आधार पर कीमतें निर्धारित करते हैं तो बाजार संरचना इस धक्के को सहन नहीं कर सकेगी । अतः प्राधिकरण ऐसी लागतों पर अगले वर्ष कीमतों के निर्धारण के समय विचार करेगा ।

खण्ड VI

परामर्श पत्र में निहित लागत कार्य–संक्षिप्त विहंगम दृष्टि

28. परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, प्राधिकरण ने आईपीएलसी सेवाएं मुहैया कराने की लागत की मांग की और उसे प्राप्त किया। इन्कमबेंट द्वारा दिए गए लागत संबंधी आंकड़ों के आधार पर परामर्श पत्र में उल्लिखित आईपीएलसी के लागत आधारित अनुमान निकाला गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मैसर्स भारती, जो आईपीएलसी का एक मात्र दूसरा प्रदाता है 2004 के प्रारंभ में केवल नॉन–रिस्टोरेबल श्रेणी की ही सेवाएं मुहैया कराता था और इसलिए उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। लागत आधारित आईपीएलसी टैरिफ प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र में अपनाई गई पद्धति में विगत की लागत का इस्तेमाल करते हुए पूर्णतः आबंटित लागत (टॉप–डाउन दृष्टिकोण) को लिया गया था। अनुमानों की सुसंगता तथा वैधता की जांच को छोड़कर वीएसएनएल (VSNL) द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों का सत्यापन करना कठिन था। इन आंकड़ों तथा कार्यविधि का इस्तेमाल करके औसत E 1 कीमत (प्रतिवर्ष 12 लाख रुपया) आकलित किया गया और इस कीमत का इस्तेमाल उच्चतर क्षमता के लिए कीमत आकलित करने के लिए किया गया और इसके लिए 1:8:23 के अनुपात में कीमत मल्टीपल का इस्तेमाल किया गया। बहरहाल, प्राधिकरण ने परामर्श पत्र में इन्कमबेंट द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों की सीमा को नोट किया और इस बारे में प्राधिकरण के कथन को नीचे उद्धृत करना प्रासंगिक होगा।

"टैरिफ की समीक्षा के दौरान, बीएसएनएल (VSNL) ने सकल ब्लाक, निबल ब्लाक, जैसे पैरामीटरों और आईपीएलसी सेगमेंट से सीधे सम्बद्ध परिचालनिक खर्चों से संबंधित आंकड़े मुहैया कराए। वीएसएनएल (VSNL) ने केबल आधारित लीज्ड सर्किटों में इस्तेमाल परिसंपत्तियों का सापेक्ष संविभाजन मुहैया कराया था जिसका सत्यापन करना सरल नहीं है। ऐसी स्थितियों में ऐसा अनुमान रहता है कि ऑपरेटर द्वारा लागत का ज्यादा अनुमान बताया जाता है। वीएसएनएल (VSNL) ने लागत आधार बढ़ाने के लिए अनुमानों का इस्तेमाल किया। वीएसएनएल (VSNL) ने केबल प्रणाली के लिए डब्ल्यूडीवी पद्धति के अंतर्गत 33% की मूल्यह्रास दर का दावा किया है। तथापि, यह पाया गया कि, सांवधिक

दायित्वों आदि की पूर्ति के प्रयोजन के लिए वीएसएनएल (VSNL) मूल्यह्रास के स्ट्रेट लाइन पद्धति का इस्तेमाल करता है और उनके तुलन–पत्र में केबल प्रणालियों की औसत आयु 10 से 25 वर्ष के बीच दर्शाई जाती है। उन्होंने कुल निवेश पर 23.66% के कर–पूर्व प्रतिफल का भी दावा किया था, जिसमें जीडीआर इश्यू के जरिए जुटाए गए 625 करोड़ रुपए की अनप्रयुक्त राशि भी शामिल है। इसके अलावा, लम्बी वार्ताओं के बाद वीएसएनएल (VSNL) द्वारा अपने 10 अक्तूबर, 2003 के पत्र के जरिए प्रस्तुत किए गए संशोधित आंकड़ों में भी ज्यादा अनुमान प्रस्तुत किया गया है। ये आकड़े भी बहुत ही असंगत है और केबल ओ एण्ड एम रि–स्टोरेशन लागत तथा सामान्य प्रशासन जनशक्ति और अन्य ओवरहेडों आदि जैसे पैरामीटरों पर इनका सत्यापन नहीं किया जा सकता है। समय–समय पर घोषित E 1 सर्किटों की संख्या में भी अन्तर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वीएसएनएल (VSNL) उस सकल ब्लाक के आधार को स्पष्ट नहीं कर पाया जिसे बिजनेस के आईपीएलसी सेगमेंट के प्रयोजन के लिए विभाजित किया गया था और परिचालनिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत ओएण्डएम के लिए ज्यादा राशि रखी गई थी। बहरहाल, हमने वीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया है और लागत आधारित उपयुक्त अनुमान प्राप्त करने के लिए कुछ आधार अनुमानों में परिवर्तन भी किया है।"

29. पृथक लेखे लागू होने के कारण वीएसएनएल द्वारा लेखांकन पृथक्करण विनियम के भाग के रूप में मुहैया कराए गए आंकड़ों का इस्तेमाल, लागत अनुमान का पता लगाने के लिए किया गया।

30. अतः पृथक लेखों में उपलब्ध आईपीएलसी की उस लेखा परीक्षित लागत का इस्तेमाल करना संभव हुआ जो ट्राई को 31 दिसम्बर, 2004 को उपलब्ध हुई थी जो विशिष्ट रूप से आईपीएलसी से लिंक है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण के पास क्षमता, बिक्री और इन्कमबेंट द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च/निवेश के और अद्यतन सूचना है। लागत आधारित टैरिफ का अनुमान लगाने के लिए इनका भी इस्तेमाल किया गया।

खण्ड VIII

लागत कार्य–परामर्श–पत्रोपरान्त

(क) पुरानी लागतों के आधार पर एफएसी का उपयोग

31. प्रासंगिक लागत अनुमानों के लिए टॉप–डाउन, एफएसी पद्धति (पुरानी लागत के साथ) का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए पृथक लेखों के लेखा परीक्षित लागत आंकड़ों को लिया गया है। मितव्ययिता के लिए आमतौर पर यह सिफारिश की जाती है कि बॉटम अप एप्रोच अथवा टॉप–डाउन एप्रोच के आधार पर टैरिफ का आकलन करने के लिए फारवर्ड लुकिंग लॉग रन इनक्रीमेंटल कास्ट (एफएलएलआरआईसी) का उपयोग किया जाए। वास्तव में अन्तरराष्ट्रीय रूप से अधिकांश विनियामक, लागत आधारित प्रभारों के निर्धारण के लिए इन्क्रीमेंटल कास्ट का ही उपयोग करते हैं, *इन्कमबेंट ने प्राधिकरण को सूचित किया था कि "लांग रन इन्क्रीमेंटल कॉस्ट अकुशल इन्कमबेंट की रक्षा नहीं करता और यह कि प्रौद्योगिकी के परिवर्तन और पूंजीगत व्यय घटने से यह प्रतिबिम्बित नहीं होता कि पुरानी औसन लागत आगे बढ़ रही है। (अर्थात् यह सम्बद्ध लागत से ज्यादा है)*

32. बहरहाल, जब एफएलएलआरआईसी आधारित टैरिफ का आकलन किया जाता है तो यह राशि वर्तमान अथवा पुराने एफएसी आधारित राशि से बहुत ही कम होती है। यद्यपि प्राधिकरण ने लागत के संदर्भ में कीमतों की कटौती पर जोर दिया। इसने इस प्रक्रिया को कायम रखने पर जोर दिया ताकि समय बीतने के साथ–साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अथवा यदि समय के साथ–साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा का वातावरण नहीं बनता तो एफएलएलआरआईसी पर ज्यादा निर्भर होकर एफएलएलआरआईसी आधारित कीमतों की ओर अग्रसर हुआ जा सके। एफएलएलआरआईसी पर मुख्यतः या पूर्णतः निर्भर होने से से बाजार को काफी ज्यादा धक्का लगेगा और इससे प्रतिस्पर्धा की दिशा में अन्तरण और अधिक कठिन हो जाएगा, इसलिए इस समय एफएलएलआरआईसी को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना महत्व दिया जाना चाहिए। इसका आशय यह है कि अधिकतम कीमत के आकलन के लिए इस्तेमाल किए गए लागत आधार में बफर की व्यवस्था है। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि वह अगले वर्ष से टैरिफ के निर्धारण के लिए धीरे–धीरे एफएलएलआरआईसी की ओर अग्रसर होगा।

आईपीएलसी के लिए लागत अनुमान

33. निम्नलिखित चार किस्मों के लागत अनुमान संभव हो सकते हैं :

(i) मार्च, 2004 की अवधि तक के लिए इन्कमबेंट सबमेरीन केबल ऑपरेशन से संबंधित आंकड़ों के आधार पर (2003–04 के तुलन–पत्र के वित्तीय आंकड़ों के अलावा पृथक लेखों में उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करके)

(ii) एक आधुनिक सबमेरीन केबल प्रणाली अर्थात् चेन्नई–सिंगापुर, की स्थापना के लिए इन्कमबेंट के नए निवेश से संबंधित आंकड़ों के आधार पर।

(iii) एक नए प्रवेशक द्वारा प्रस्तुत दीर्घकालिक आधार पर केबल के लीज के लिए किए गए आईआरयू भुगतान के आंकड़ों तथा दीर्घकालिक आधार केबल के लीज के लिए आईआरयू भुगतान और लैंडिंग स्टेशन की सुविधाओं के लिए एक अन्य नए प्रवेशक के निवेश के संयोजन के आधार पर।

(iv) आईएलडीओएस के सबमेरीन केबल प्रणालियों के अधिग्रहण की लागत से संबंधित आंकड़ों के आधार पर।

34. अधिग्रहण (अर्थात् ऊपर मद IV) की लागत के आंकड़े मांगे गए थे परन्तु वे अभी मुहैया नहीं कराए गए हैं। अतः विभिन्न स्रोतों से सबमेरीन केबल प्रणालियों के अधिग्रहण की लागत से संबंधित सूचना एकत्र की गई।

35. पिछले 2–3 वर्षों के दौरान केबल प्रणाली के अधिग्रहण से संबंधित सूचना से उस क्षमता के लिए लागत की कमी का अन्दाजा लगता है जिसे इन आईएलडीओएस द्वारा आईपीएलसी सेक्टर में बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के लिए इन्कमबेंट द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में एफएलएजी के लिए 2002 के दौरान 2 बिलियन डॉलर की परिसंपत्ति हानि तथा टायको के लिए 665 मिलियन डॉलर को बट्टे खाते डाला गया दर्शाया है। (अर्थात् एक डॉलर के 44 रु0 विनिमय दर के हिसाब से 8,800 करोड़ रुपये तथा 3,000 करोड़ रुपए)

36. यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागत आधारित टैरिफ, भारत में आईएलडीओएस द्वारा सबमेरीन केबल प्रणालियों के अधिग्रहण के लिए किए जाने वाले बहुत ही कम स्तर के निवेश/लागत पर आधारित नहीं है क्योंकि यह प्रति E 1 मौजूदा निवेश का अंश मात्र का ही परिचायक है। इन लागतों के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप आईपीएलसी की लागत आधारित कीमत में भारी गिरावट होगी और यह अन्तरण अवधि के दौरान बाजार को कोई बड़ा धक्का पहुंचाए बिना लागत आधारित अधिकतम टैरिफ विनिर्दिष्ट करने के प्राधिकरण के प्रयासों के भी विरूद्ध होगा।

37. एक नए प्रवेशक ने दीर्धकालिक आधार पर केबल की लीजिंग के लिए उनके द्वारा भुगतान किए गए आईआरयू लीज किराए से संबंधित आंकड़े मुहैया कराए हैं। दूसरे नए प्रवेशक ने केबल लैंडिंग सुविधा के लिए किए गए निवेश तथा उसके द्वारा भुगतान किए गए आईआरयू लीज किराए के आंकड़े मुहैया कराए। इन आंकड़ों के आधार पर E 1 क्षमता के लिए लागत अनुमानों का पता लगाया गया है। इन्कमबेंट की पुरानी प्रणालियों में लगे निवेश के मामले में पुरानी लागत से संबंधित लागत अनुमान की तुलना में इन अनुमानों में भी बहुत की कम कीमत दी गई है। जैसा कि पहले कहा गया है प्राधिकरण ने बाजार को कोई बड़ा धक्का लगाए बिना खासतौर पर इन्कमबेंट को, कोई बड़ा धक्का लगाए बिना सुचारू अन्तरण करने का निर्णय लिया है, इसलिए अधिकतम टैरिफ के निर्धारण के लिए नए प्रवेशकों के लागत अनुमान को इस समय उपयुक्त नहीं समझा गया है।

38. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि वीएसएनएल ने 2004 में चेन्नई तथा सिंगापुर के बीच नई केबल प्रणाली का और चेन्नई में लैंडिंग स्टेशन का निर्माण किया। यह केबल प्रणाली प्रचालन के लिए तैयार है। वीएसएनएल द्वारा स्थापित इस नए केबल प्रणाली के माध्यम से आईपीएलसी सेवा मुहैया कराने की लागत अनुमान, उनके द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किए गए हैं। E 1 क्षमता के हिसाब से लागत का अनुमान प्राप्त करने के लिए क्षमता उपयोग के एक रेंज पर विचार किया गया और इन्कमबेंट द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत जानकारी के अनुसार जिसके लिए सापेक्ष रूप से क्षमता का कम उपयोग हिसाब में लिया गया है। प्राधिकरण ने पाया कि इनमें भी लागत आधारित टैरिफ,

वीएसएनएल की अपनी पुरानी केबल प्रणालियों की पृथक लेखाओं से प्राप्त टैरिफ से काफी कम है। ऊपर उल्लिखित कारणों से प्राधिकरण इन अपेक्षाकृत कम लागतों पर भी बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा है। यहां तक कि वीएसएनएल के लिए भारित औसत लागत के लिए भी नहीं। इस प्रकार लागत आधारित टैरिफ में भी पर्याप्त बफर की व्यवस्था की गई है।

39. प्राधिकरण ने नोट किया कि सबसे अधिक विस्तृत सूचना इन्कमबेंट के पृथक लेखों से प्राप्त हुई और लागत आधारित अनुमान, विश्लेषण तथा विस्तृत जांच के बाद प्राप्त की गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है दूसरे आंकड़ों के आधार पर भी अनुमान लगाया गया और हमारे विश्लेषण में इनसे भी उपयोगी सहायता प्राप्त हुई तथा लागत आधारित टैरिफ, इन्कमबेंट के पृथक लेखों से निकाला गया। वैकल्पिक लागत सूचना पर आधारित अनुमान कम था तथा नियामक नीति के तौर पर विनियामक के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा के निर्धारण के लिए इस प्रकार की सूचना का इस्तेमाल करना उचित था। प्राधिकरण ने प्रणाली को कोई बड़ा धक्का न लगने तथा निर्दिष्ट अधिकतम सीमा में उपयुक्त बफर रखने के लिए इन वैकल्पिक कम अनुमानों का इस्तेमाल नहीं किया।

क्षमता उपयोग

40. प्राधिकरण के पास जुलाई, 2004 को वीएसएलएल के पास उपलब्ध वास्तविक क्षमता की सूचना थी। प्राधिकरण ने अप्रैल से जुलाई, 2004 की अवधि में वीएसएनएल द्वारा किए गए पूंजीगत खर्च/निवेश की जांच की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 2003–04 के पृथक लेखों के लिए पूंजीगत खर्च को जुलाई, 2004 में उपलब्ध इस क्षमता में आवंटित किया जा सकता है अर्थात् मार्च, 2004 के अंत के पूंजीगत खर्च को जुलाई, 2004 में उपलब्ध क्षमता को बढ़ाने का कारण समझा जा सकता है।

41. अगला कदम कुल उपलब्ध क्षमता की जांच करना होगा जिसके लिए लागत प्रति E1 औसत लागत का निर्धारण करने के लिए लागत आबंटित की जा सकती है। प्राधिकरण के पास विभिन्न क्षमताओं अर्थात् E1, DS-3 तथा STM-1 की मार्च, 2004 से सितम्बर, 2004 से संबंधित आंकड़े हैं। जुलाई, 2004 में उपलब्ध क्षमता के 60% से कम क्षमता सितम्बर,

2004 में वीएसएनएल द्वारा बेची गई। क्षमता के इस स्तर के लिए पूंजीगत व्यय तथा परिचलन व्यय को प्रति E1 के आधार पर आबंटित किया जाता है।

42. वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत किए गए विकास परिदृश्य को देखें तो यह कार्यान्वयन अवधि के दौरान सम्बद्ध क्षमता के उपयोग का कम अनुमान लगाना प्रतीत होता है। कार्यान्वयन की अवधि के दौरान वीएसएनएल की बिक्री योग्य क्षमता कई गुणा बढ़ेगी और इसकी लागत जुलाई, 2004 के लिए उपलब्ध क्षमता के लिए किए गए आकलन के काफी कम होगा। इस प्रकार यदि प्राधिकरण नई जुड़ी क्षमता के तुलनात्मक रूप से कम अनुमान पर निर्भर करे तो औसत लागत में काफी कमी आएगी। इन्कमबेंट द्वारा नई जोड़ी गई क्षमता उसकी कुल क्षमता के 96% से ज्यादा है और इस प्रकार इस सीमा तक पुरानी केबल प्रणालियों की पुरानी लागत के आधार कार्यान्वयन अवधि के दौरान वीएसएनएल के लिए प्राप्त होने वाले लागत के अनुमान से काफी ज्यादा होगा। बहरहाल, प्राधिकरण ने बाजार को कोई बड़ा धक्का पहुंचाए बिना इन्क्रीमेंटल लागत का दृष्टिकोण न अपनाकर प्रतिस्पर्धा की ओर सुगमता से अग्रसर होने के लिए इस परिवर्तन को सुसाध्य बनाने के लिए एक बफर की व्यवस्था की है, इसलिए प्राधिकरण वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत 2003–04 के आंकड़ों तथा 2004 के दौरान बिक्री/क्षमता आदि से संबंधित दूसरे आंकड़ों के आधार पर औसत लागत का इस्तेमाल किया। कार्यान्वयन अवधि 2005–2006 है।

पूंजीगत व्यय

43. पूंजीगत व्यय में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (Return on Capital Employed (आरओसीई) और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन शामिल हैं। इन व्ययों के आकलन की पद्धति की चर्चा नीचे की गई है :

(क) नियोजित पूंजी – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखा बहियों तथा अन्य प्रलेखों का रखरखाव) नियम, 2002 द्वारा निर्धारित बहियों के रखरखाव के तरीके के संबंध में 8.11.2003 को राजपत्र में अधिसूचित डीओटी के आदेश सं0

7–4/2001–टैरिफ में नियोजित पूंजी की परिभाषा निबल अचल परिसंपत्तियों, संचालन पूंजी तथा चालू पूंजीगत कार्यों के जोड़ के रूप में दी गई है। लेखा पृथक्करण रिपोर्ट में, सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित पूंजी को उसके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उत्पादों को आवंटित किया गया है। वीएसएनएल (VSNL) ने आईपीएलसी पर नियोजित पूंजी को पृथक लेखों में आवंटित किया है। प्राधिकरण ने इन राशियों पर निम्नानुसार कतिपय समायोजन कियेः

(i) वह रकम जो आईपीएलसी से संबंधित न हो–वीएसएनएल (VSNL) के पृथक लेखों में आईपीएलसी के लिए नियोजित पूंजी की राशि में टाटा टेलीसर्विसेज लि0 में इसके निवेश का भाग और जीडीआर इश्यू से जुटाया गया धन है, जो इस समय बैंक में जमा है, शामिल है। इन मदों को लागत के आकलन के लिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये आईपीएलसी से संबंधित नहीं है, जिसके लिए लागत का आकलन किया गया है। वीएसएनएल (VSNL) ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि इस राशि को घटाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि टीटीएसएल में निवेश वीएसएनएल (VSNL) के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है इसलिए इसे परिचालित पूंजी समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, वीएसएनएल (VSNL) ने यह भी दावा किया कि जीडीआर इश्यू के दौरान जुटाई गई राशि इस्तेमाल के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन हैं और इस पर लागत भी लगती है। उसने इसे नियोजित पूंजी का भाग माना। प्राधिकरण इस विचार से सहमत नहीं था। ये निधियां आईपीएलसी के परिचालन से सम्बद्ध नहीं थी और उनसे संबंधित लागत को आईपीएलसी के ग्राहकों पर नहीं डाला जाना चाहिए, इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया है और नियोजित पूंजी को इन दो मदों में समायोजित किया गया है।

(ii) सैटेलाइट के लिए पूंजीगत व्यय को हटाना–प्राधिकरण केवल केबल के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट कर रहा है न कि सैटेलाइट आईपीएलसी के लिए। अतः सैटेलाइट के लिए आबंटित लागत को हटाया जाना आवश्यक है। इन्कमबेंट द्वारा प्रस्तुत 2003–04 के आईपीएलसी सेगमेंट के पृथक लेखों में केबल सर्किट तथा सैटेलाइट सर्किट दोनों की लागत शामिल है। आईपीएलसी सेंगमेंट के लिए नियोजित सैटेलाइट परिसंपत्तियां "प्राइसिंग ऑफ आईपीएलसी" (वीएसएनएल की ओर से बोस्टन कंसल्टिंग

ग्रुप द्वारा तैयार) रिपोर्ट में, जिसे वीएसएनएल ने प्राधिकरण को प्रस्तुत किया है, अलग से दी गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएलसी से सम्बद्ध सैटेलाइट परिसंपत्तियां लगभग 4% हैं। नियोजित पूंजी केवल इसी सीमा तक समायोजित की गई है यद्यपि कम्पोजिट लागत में सैटेलाइट के लिए परिसंपत्तियों के लेखागत सकल ब्लाक का अनुपात प्राधिकरण को प्राप्त दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा है।

(ख) आरओसीई : प्राधिकरण ने परामर्श–पत्र में (पत्र सं0 10/2004) में 14.42% के आरओसीई का इस्तेमाल किया है। वीएसएनएल ने प्राधिकरण को सूचित किया कि यदि आरओसीई प्राप्त करने के लिए और हाल की लागत अनुमान को लिया जाए तो 99:1 के इक्विटी–ऋण अनुपात तथा प्रतिफल ऋण तथा इक्विटी पर प्रतिफल क्रमशः 8% और 18.92% के आधार पर कर–पूर्व उपयुक्त आरओसीई 18.79% होगा। 14.42% के अपने अनुमान के लिए प्राधिकरण ने अपने परामर्श–पत्र में इक्विटी–ऋण का अनुपात 96:4 लिया था।

44. प्राधिकरण ने वीएसएलएल के इस कथन की जांच की और नोट किया कि इक्विटी–ऋण संरचना, सामान्य तथा समुचित पूंजी संरचना से काफी भिन्न थी। इस संबंध में परामर्श–पत्र अनुपात के उपयोग पर और टिप्पणियां प्राप्त की गईं। इसके अलावा, परामर्श–पत्र में आरओसीई एक सामान्य उद्योग के आरओसीई जैसा था। यह एक तरफा नहीं था। इसे वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर ही तैयार किया गया था। विनियामक के लिए यह उपयुक्त है कि वह उन आंकड़ों (पूंजी संरचना से संबंधित आंकड़ों सहित) में समायोजन करे जो असामान्य हो तथा ऑपरेटर की अकुशलता दर्शायें। प्राधिकरण ने उद्योग में लगे दूसरे ऑपरेटरों के औसत आरओसीई की जांच की और वह आंकड़ा 14% कम आया। वीएसएनएल (VSNL) के ऊपर उल्लिखित प्रस्तुति में यदि हम इक्विटी–ऋण अनुपात को 60:40 में बदलें, जो एक कुशल पूंजी संरचना के लिए एक उपयुक्त अनुपात है, तो आरओसीई, प्राधिकरण द्वारा परामर्श–पत्र में इस्तेमाल की गई राशि के समान ही होगी। वास्तव में, प्राधिकरण ने पहले किसी अन्य संबंध में इक्विटी–ऋण का अनुपात 1:1 लिया। यदि इस अनुपात का इस्तेमाल किया जाए तो

आरओसीई और कम 13.46% होगी। वीएसएनएल (VSNL) ने एक विनियम (राजपत्र में प्रकाशित) के अन्तर्गत प्राधिकरण को 31 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किए गए लेखा परीक्षित लेखा पृथक्करण विवरण में डब्ल्यूएसीसी (Weighted Average cost of Capital) के रूप में 14.42% का इस्तेमाल किया है। अतः इन्हीं कारणों से प्राधिकरण ने 14.42% के आरओसीई का इस्तेमाल जारी रखा।

(ग) मूल्यह्रास–आईपीएलसी सेगमेंट के सैटेलाइट आधारित परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास लेखा पृथक्करण विवरण में दिए गए आईपीएलसी सेगमेंट के लिए मूल्यह्रास शीर्ष के अंतर्गत 4% का समायोजन किया गया है।

45. वीएसएनएल ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि पूंजीगत लागत के लिए मूल्यह्रास का मूल्य ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यद्यपि मूल्यह्रास की राशि 18 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर आकलित की गई है जबकि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए केबल का आर्थिक काल 5 से 8 वर्ष ही होता है। वीएसएनएल ने इस बात का समर्थन यह कह कर किया *"एसएमडब्ल्यू 3 और एसएएफई सहित हाल की परिसंपत्तियों पर वीएसएनएल ने पिछले 7–8 वर्षों में निवेश किया है। मौजूदा परिसंपत्तियों का आर्थिक–काल 8 वर्ष से और कम कर दी गई है। एसएमडब्ल्यू–4 के चालू होने/स्थायित्व पाने के बाद एसएमडब्ल्यू–2, जिसे 1995 में चालू किया गया था, को अगले वर्ष रिटायर होना है।"*

46. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि यह आईपीएलसी, के लिए वास्तविक मूल्यह्रास की राशि इस्तेमाल कर रहा है, जिसे वीएसएनएल द्वारा एक विनियम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2004 को प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए परीक्षित पृथक लेखा में दिया गया था। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि वीएसएनएल का यह दावा सही नहीं है कि अब मूल्यह्रास के प्रयोजन के लिए एक केबल का कार्यकाल 10 वर्ष से कम रहता है। 2003–04 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वीएसएनएल (VSNL) ने टाटा इंडिकॉम

इंडिया सिंगापुर केबल (TIIS Cable) के बारे में कहा है कि *"25 वर्ष की अनुमानित कार्यकाल के साथ इस नए केबल से भारत की पेस्फिक के रास्ते एशिया पेस्फिक रीजन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ काफी कनेक्टिविटी बढ़ेगी।"* (जोर दिया गया है वार्षिक रिपोर्ट का पृष्ठ 12)। यदि हम कार्यकाल के इस अनुमान का इस्तेमाल करें तो मूल्यह्रास की राशि और भी कम होनी चाहिए। बहरहाल, प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया और यह पृथक लेखे में इसे प्रस्तुत परीक्षित लेखों पर ही निर्भर रहा है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि केबल सामान्यतः अपने वास्तविक रूप में कम से कम ट्राई की गणना में आकलित अपने पूरे कार्यकाल तक काम में आता रहता है। इसके अलावा, नई मोड्यूलेशन तकनीक की उपलब्धता से बहुत की कम लागत पर केबल की क्षमता में भारी वृद्धि की जा सकती है।

47. वीएसएलएल द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आंकड़ों के आधार पर प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि विगत में बहुत उंची कीमतें थी (2000 में आईपीएलसी की कीमतें 163.7 लाख रुपए थी), जिसने निवेश पर काफी प्रतिफल पहले ही प्रदान कर दिया है।

परिचालन व्यय

48. 2003–04 के पृथक लेखों में दिए गए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत परिचालन व्यय को परिचालन व्यय के निर्धारण के लिए हिसाब में लिया गया है। इस शीर्ष के अन्तर्गत व्यय की वे मदें, जिन्हें प्राधिकरण ने सबमेरीन केबल के माध्यम से आईपीएलसी मुहैया कराने के प्रयोजन के लिए संगत नहीं समझा है, उन्हें परिचालन व्यय के निर्धारण के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है। इनमें लैंडलाइन के किराये तथा सैटेलाइट आधारित आईपीएलसी का परिचालन व्यय शामिल है।

49. पृथक लेखों में दिखाए गए लैंडलाइन के किराया प्रभार के संबंध में वीएसएलएल ने स्पष्ट किया है कि "खर्च की इस मद में आईपीएलसी सेवाओं के लिए घरेलू कनेक्टिविटी प्रदान करने के वास्ते दूसरे सेवा प्रदाताओं से प्राप्त किए गए घरेलू बैंडविथ के लीज प्रभार शामिल हैं"। इनके किए टैरिफ, आईपीएलसी से अलग से प्रभारित किया जाता है। सैटेलाइट के परिचालन खर्च के संबंध में प्राधिकरण ने नोट किया कि वीएसएनएल द्वारा

प्रस्तुत लागत में विसंगति है, जिसमें संगत लागत का अनुमान ज्यादा दिखाया गया है। वित्त वर्ष 2003–04 के लिए "सैटेलाइट चैनलों के लिए किराया" शीर्ष के अंतर्गत अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में (अर्थात् वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी के कम्पोजिट लेखे) वीएसएनएल ने सैटेलाइट से संबंधित परिचालन व्यय 172.17 करोड़ रु0 वर्गीकृत किए हैं। अपने पृथक लेखों में वीएसएनएल ने "सैटेलाइट चैनलों के लिए किराया" नाम का कोई लागत शीर्ष नहीं रखा है। अपने पृथक लेखों में इसमें एक और शीर्ष "इंटरनेशनल बैंडविथ प्रभार" दिया है। इसमें भी कुछ अन्य लागतों के साथ सैटेलाइट के किरायों की लागत दी गई है। पश्चातवर्ती शीर्ष वार्षिक कम्पोजिट लेखे में नहीं है और इसलिए आंकड़े समायोजित करने की आवश्यकता थी, जिसे प्राधिकरण ने किया क्योंकि वीएसएनएल (VSNL) द्वारा बाद में प्रस्तुत सूचना भी दर्शाती है कि सैटेलाइट के लिए दर्शाए जाने वाले संगत परिचालनिक लागत का काफी हद तक कम अनुमान लगाया जा रहा था। समायोजन के इसके प्रयासों, इसके उपयोग के पैटर्न तथा "इन्टरनेशनल बैंडविथ प्रभार" के अंतर्गत अन्य लागत तत्वों के महत्व को देखते हुए प्राधिकरण ने आईपीएलसी के लिए लागत आधारित टैरिफ की गणना परिचालनिक लागत का समायोजन करके की है, ताकि 172.17 करोड़ रु0 के सैटेलाइट चैनल के किराये का हिसाब पूरी तरह तथा उपयुक्त रूप से पृथक गतिविधियों में हो जाए, जिसे वीएसएनएल द्वारा पृथक लेखों में दिया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पृथक लेखों में यदि राशि के दो तिहाई को आईपीएलसी से भिन्न सेवाओं के लिए "इंटरनेशनल बैंडविथ प्रभार" को सैटेलाइट के किराए के रूप में दर्शाया जाए तो आईपीएलसी के पृथक लेखों में दर्शाए गए 'इन्टरनेशनल बैंडविथ प्रभार' की पूरी राशि को सैटेलाइट चैनलों के किराए के रूप में आवंटित किया जाना होगा।

50. ऊपर उल्लेख किए गए सभी संगत मुद्दों पर विचार करने के बाद प्राप्त पूंजीगत व्यय तथा परिचालनिक व्यय के आधार पर प्राधिकरण ने आईपीएलसी हॉफ सर्किट का टैरिफ E1 के हिसाब से निर्धारित करने का निर्णय लिया। ऊपर उल्लिखित पद्धति का इस्तेमाल करके उपर्युक्त अनुमान के आधार पर प्रति E1 औसत लागत 7.40 लाख रूपए से 9.00 लाख रुपए के रेंज में है। E 1 के मूल्य का निर्णय करते समय (लागत अनुमान के आधार पर) प्राधिकरण ने उस अनुपात

जिसे उच्चतर क्षमताओं के लिए कीमत मल्टीपल के रूप में प्रस्तावित किया जाना है, को भी ध्यान में रखा। उच्चतर क्षमताओं के लिए उनके तकनीकी गुणांक (अथवा क्षमता का तकनीकी मल्टीपल) की तुलना में E1 के संबधं में कीमत मल्टीपल को कम करने का अर्थ यह होगा कि एक ऐसी लागत राशि है जिसे तब तक वसूल नहीं किया जा सकता जब तक E1 के लिए टैरिफ की अधिकतम सीमा न बढ़ाई जाए। उच्चतर क्षमता के मल्टीपल, जिसकी चर्चा अगले खण्ड में की गई है, को ध्यान में रखकर प्राधिकरण ने ऐसा किया है।

51. उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखकर और इस तथ्य को देखते हुए भी कि चाहे गंतव्य/रूट कोई भी क्यों न हो यह अधिकतम सीमा सभी दूरियों तथा सभी केबल प्रणालियों के लिए लागू होगी, प्राधिकरण ने विनिश्चय किया है कि आईपीएलसी के लिए अधिकतम टैरिफ प्रति E-1, 13 लाख रुपए किया जाए। यहां विस्तृत आंकडे नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि प्राधिकरण ने इन्कमबेंट के वाणिज्यिक रूप से गोपनीय आंकडों का इस्तेमाल किया है । प्राधिकरण के लिये यह वैध होता कि वह नए प्रवेशक या यहां तक कि इन्कमबेंट की काफी कम लागत अनुमान का इस्तेमाल करता, परन्तु प्राधिकरण ने कम कीमत की ओर सुगमता से अग्रसर होने के लिए ऐसा नहीं किया और लागत आधारित टैरिफ में काफी बफर रखा। इस प्रकार निर्धारित अधिकतम टैरिफ सबसे दूर के गंतव्य के लिए है और ऑपरेटर इस बात के लिए स्वतंत्र है कि विभिन्न गंतव्यों/मार्गों के लिए वे इस अधिकतम टैरिफ से कम टैरिफ की पेशकश कर सकते हैं।

खण्ड VIII

डीएस–3 तथा एसटीएम–1 का कीमत निर्धारण

52. बैंडविथ, बहुत सी अन्य वस्तुओं की तरह ही जब बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है तो वह प्रति यूनिट आधार पर सस्ती हो जाती है। इसके अतिरिक्त उच्चतर क्षमता के साथ अपेक्षित औजारों, विपणन तथा बिक्री की लागत भी घटती है। ग्लोबल मल्टीपल्स के विश्लेषण (प्रीमेट्रिका, आईएनसी 2004 वाल I : सबमेरीन नेटवर्क्स) से पता चलता है कि E1 से DS-3 की कीमत के मल्टीपल्स अक्सर E 1 सर्किट की कीमत के 4–7 गुणा के रेंज में रहते हैं जबकि E 1 से STM-1 के मल्टीपल E 1 कीमतों के 8–17 गुणा के रेंज में होते हैं (नीचे तालिका देखें)

स्रोत	अनुपात (ई1ःडीएस–3ःएसटीएम–1)
टेलिजियोग्राफी – उच्च	1:7:17
टेलिजियोग्राफी – निम्न	1:4:8

इसके अतिरिक्त इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कीमत अनुपात को न्यूनतम क्षमता अर्थात् E 1 की कीमतों के साथ देखा जाना है। भारत में आईएलडीओएस द्वारा पेश किए गए मौजूदा टैरिफ E1,DS-3 तथा STM-1 के बीच का अनुपात, इन क्षमताओं के लिए अन्तरराष्ट्रीय कीमत के अनुपात की तुलना में बहुत ज्यादा है। विभिन्न क्षमताओं की बिक्री से संबंधित आंकड़ों से यह पता चलता है कि निकट भविष्य में आईपीएलसी के मांग परिदृश्य में उच्चतर क्षमता की ही प्रभुत्व रहेगा। अतः E 1 क्षमता के लागत अनुमान प्राप्त कर लेने के बाद अगला कदम DS-3 तथा STM-1 की कीमत का निर्णय करना होगा ताकि सेवा प्रदाता को उसके द्वारा सभी क्षमताओं की सेवाओं के प्रावधान करने के लिए किए गए खर्च की औसत रूप से भरपाई हो जाए। इन क्षमताओं की E1 के हिसाब से समतुल्य क्षमता का गुणांक 1:21:63 है। इन क्षमताओं के कीमत निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले गुणांक को प्राप्त किया जाना है। इसक उद्देश्य, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऐसी कीमतें प्राप्त करना है जो उपयुक्त हों और जिनसे लागत पर्याप्त रूप से कवर हो जाती हो।

53. इन्कमबेंट द्वारा सप्लाई किए गए लागत के आंकड़ों तथा इस ज्ञापन के पहले के खण्डों में चर्चा किए गए अन्य लागत आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि बैंडविथ की औसत लागत में निवेश तथा परिचालन लागत दोनों के हिसाब से, समय के साथ–साथ गिरावट आई है। प्रौद्योगिकी की उन्नति के कारण यह रूझान भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, इसका आशय यह है कि अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की सीमान्त लागत, औसत लागत अनुमान से काफी कम है और यह भविष्य में और कम होगी। प्राधिकरण के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, जिसमें वीएसएनएल (VSNL) तथा दूसरे आईएलडी ऑपरेटरों द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए आंकड़े शामिल हैं तथा विभिन्न देशों के आईपीएलसी के वर्तमान लीज किरायों के आधार पर तथा आईपीएलसी के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था, के लिए किए गए निवेश के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को देखते हुए तथा विभिन्न क्षमताओं से भारित आधार पर लागत की भरपाई सुनिश्चित करने के बाद DS-3 और STM-1 क्षमताओं के लिए कीमत मल्टीपल क्रमशः 8 और 23 निर्धारित किया गया है। अधिदेशाधीन निर्धारित अधिकतम टैरिफ के परिणामस्वरूप इन्कमबेंट के मौजूदा सूचीबद्ध टैरिफों में E1, DS-3 तथा STM-1 के मामले से क्रमशः 35%, 71% और 70% कमी होगी। (अनबंध–क, परिशिष्ट 1 की तालिका–4 देखें) इनकी अन्तरराष्ट्रीय कीमतों से (दिसम्बर, 2004 की बाजार कीमतों पर) तथा E 1 की तुलना में उच्चतर क्षमताओं की कीमतों के अनुपात से भी तुलना की गई, जिन्हें आगे दिया जा रहा है।

आईपीएलसी कीमतों का अन्तरराष्ट्रीय कीमतों (एशियन रीजन) से तुलना

E 1 कीमतें तथा कीमत मल्टीपल्स

	(1)	(2)	(3)	(4)
देश	E1 कीमत अमेरिकी डॉलर '000	DS-3 कीमत अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	STM-1 कीमत अमेरिकी डॉलर मिलियन	अनुपात (1):(2):(3)
जापान	23	0.10	0.2	1:4:8
द0 कोरिया	23	0.10	0.2	1:5:10
हांगकांग	24	0.12	0.3	1:5:11
सिंगापुर**	33	0.17	0.3	1:5:11
भारत (वर्तमान)*	39	0.66	1.9	1:18:50
भारत (अधिकतम सीमा निर्धारित दर रु0)	29.55	0.24	0.68	1:8:23

अन्तरराष्ट्रीय आंकड़ों का स्रोत : एर्नस्ट एण्ड यंग/टेलिजियोग्राफी

नोट : अमेरिकी डॉलर = 44 रु0

*रियायती कीमतें

**सिंगापुर की E-1 की कीमतें, अन्य बातों के साथ साथ DS-3 तथा STM-1 के लिए कम मल्टीपल के कारण, ज्यादा हैं ।

54. वीएसएलएल ने प्राधिकरण को प्रस्तुत अपने अनुरोध–पत्र में कहा कि यद्यपि प्राधिकरण ने एनएलडीओ के कीमत निर्धारण के लिए 1:21:63 का अनुपात अनुमोदित किया था, परन्तु इसने आईपीएलसी के कीमत निर्धारण के लिए 1:8:23 का प्रस्ताव किया है। तथापि, इन दोनों सेवाओं के लिए एक समान ही प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें मल्टीप्लेक्सिंग/डिमल्टीप्लेक्सिंग की सम्बद्ध लागत भी समान अनुपात में होती हैं। इस संबंध में प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि घरेलू लीज्ड सर्किट के लिए लागू अधिकतम सीमा को संशोधित करने के लिए अलग परामर्श–पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और इस मुद्दे पर भी प्राधिकरण समुचित कार्रवाई करेगा।

खण्ड IX

परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए मुद्दों की और जांच

55. परामर्श प्रक्रिया में उठाए गए कई मुद्दों की चर्चा पूर्ववर्ती नोटों में की गई है। वीएसएनएल (VSNL) ने 23 फरवरी, 2005 के अपने पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को अपनी प्रस्तुति में यही मुद्दा खासतौर पर एक बार फिर उठाया। इन मुद्दों पर पुनः नीचे दिए गए पैराओं में चर्चा की जाती है :

"भारत में आईपीएलसी की कीमतें तुलनीय बेंचमार्क के अनुसार हैं।"

56. इस तर्क का प्रमाणों के साथ जोरदार प्रतिवाद इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत खण्डों में किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में आईपीएलसी टैरिफ में लगभग 10% की गिरावट आई (कम्पाउंट वार्षिक विकास दर) जबकि दूसरे प्रमुख बाजारों में गिरावट 45% (सीएजीआर) रही। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अपनी प्रस्तुति में इन्कमबेंट द्वारा तुलना भारतीय आईपीएलसी टैरिफ तथा दूसरे देशों के आईपीएलसी लीज किरायों की सूचीबद्ध कीमतों के आधार पर की गई है। ऐसी स्थिति में बाजार के औसत वास्तविक कीमतों से तुलना करना संगत है न कि सूचीबद्ध कीमतों से इसे देखते हुए, प्राधिकरण ने बाजार की कीमतें अन्तरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्राप्त किए, जिसे पता चलता है कि भारत में आईपीएलसी की कीमतों में गिरावट अन्यत्र आई गिरावट के समान नहीं है और न ही कीमतें लागत के अनुसार हैं। इन्कमबेंट का यह तर्क पूरी तरह सही नहीं है कि अन्तरराष्ट्रीय बैंडविथ की कीमतों में तेजी से आई कमी अध्याय 11 दिवालियापन से सुरक्षा से सम्बद्ध है। वास्तव में, इस स्थिति में इन्कमबेंट ने भी क्षमता बहुत की कम कीमत पर प्राप्त की है, जिस पर हमने विचार नहीं किया है। बजाय इसके, एफएसी टॉप डाउन एप्रोच पर आधारित लागत अनुमान का पता लगाने के लिए प्राधिकरण को वीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत 2003–04 के पृथक लेखों का इस्तेमाल किया गया । जुलाई 2004 में उपलब्ध क्षमता से पता चलता है कि वीएसएनएल द्वारा निर्धारित कीमतें, लागत से बहुत ज्यादा हैं। अलग से भी साक्ष्य जुटाए गए जिनसे पता चलता है कि सबमेरीन केबल प्रणाली बिछाने की लागत काफी कम हो गई है। (खण्ड III में चर्चा की गई) इसके अलावा, चूंकि लागत घट रही है और टैरिफ की अधिकतम सीमा 2005–06 में लागू की

जाएगी इसलिए पद्धति में पहले से उपलब्ध मार्जिन के अलावा पिछली अवधि की लागत आधारित अधिकतम टैरिफ तथा क्षमता के आधार पर भी मार्जिन उपलब्ध होगा।

अन्तरराष्ट्रीय बैंडविथ अन्तरराष्ट्रीय लागत का एक छोटा सा भाग है

57. प्राधिकरण को अपनी एक प्रस्तुति में वीएसएनएल (VSNL) ने अनुरोध किया कि इन्टरनेशनल बैंडविथ, आईटी तथा आईटीई सम्बद्ध सेवाओं की लागत संरचना तथा ब्राडबैंड सेवा मुहैया कराने की लागत का एक बहुत छोटा भाग है, इसलिए उनका तर्क था कि आईपीएलसी में टैरिफ की कटौती से उन सेवाओं को मुहैया करने की लागत में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनके लिए इन्टरनेशनल बैंडविथ की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण ने इस तथ्य को नोट किया और यह दोहराया कि बैंडविथ, आईटी तथा आईटीई सेवाओं तथा सामान्यतौर पर पूरे देश में तथा खासतौर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने यह भी देखा है कि बैंडविथ की लागत, सामान्यतौर पर देश में ब्राडबैंड तथा इन्टरनेट सेवाओं की व्यवस्था, करने के लागत का एक बड़ा भाग है (कुल मासिक लागत का 45% से ज्यादा)। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि इस प्रकार की कीमतों से उनको समान अवसर प्राप्त नहीं रहता जो सेवा प्रदान करने के लिए आईपीएलसी का इस्तेमाल तो करते हैं पर जिनके पास अपनी आईपीएलसी नहीं होती है और जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मकम बाजार में आईपीएलसी के मालिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। इन कारकों को ध्यान में रखकर विनियामक का काम है कि क्या किसी खास सेवा को विनियमित किया जाए तथा ऐसी सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए। प्राधिकरण का निर्णय इसी प्रकार के निर्णय पर आधारित है, जैसा कि व्याख्यात्मक ज्ञापन में दर्शाया गया है।

"हब तथा हब (स्पोक) और स्पोक्स के बीच लिंक के लिए कीमतें अलग है"

58. इन्कमबेंट ने प्राधिकरण से यह भी अनुरोध किया कि कुछ एशियायी देशों में मौजूद आईपीएलसी की कतिपय निम्न कीमतें वास्तव में हबों के बीच की कीमतें हैं और ऐसे हबों के बीच आईपीएलसी की कीमतें उच्च ट्रैफिक घनत्व के कारण कम होती हैं। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि आईपीएलसी के लिए टैरिफ वास्तविक लागत के आधार पर

निर्धारित किए गए हैं और उस लागत में भी पर्याप्त मार्जिन तथा बफर की व्यवस्था की गई है।

"बाजार के विनियमन से निवेश प्रभावित होगा"

59. वीएसएनएल (VSNL) की राय थी की बाजार को विनियमित करने के किसी भी प्रयास से निवेश प्रभावित होगा और इस प्रकार विकास भी अवरूद्ध होगा। उनका यह भी विश्वास था कि इससे ग्राहकों के लिए पैकेजों की पेशकश करने में भी जटिलता आएगी। प्राधिकरण का विचार है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार अधिकतम कीमत निर्धारित करने से भावी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वर्तमान क्षमता का काफी कम उपयोग हो रहा है और जैसा कि नोट में अन्यत्र चर्चा की गई है पुरानी लागत को अपनाने और उन पर लागत अनुमान में बफर मुहैया कराने के कारण लागत अनुमान में पर्याप्त मार्जिन पहले ही मुहैया है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से बहुत उंची कीमत मौजूद होने के कारण इन्कमबेंट ने इन सुविधाओं से भारी राशि अर्जित की है। चूंकि आईपीएलसी की प्रस्तावित कीमतें अधिकतम सीमा के रूप में होगी इसलिए ऑपरेटर उपभोक्ताओं को किसी भी पैकेज की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

"सिंगल आईपीएलसी दर से ग्राहकों का उत्पाद विकल्प प्रतिबंधित होगा"

60. वीएसएनएल ने कहा है कि सिंगल आईपीएलसी दरों से ग्राहकों का उत्पाद विकल्प प्रतिबंधित होंगे और इस प्रकार बाजार में जटिलता उत्पन्न होगी। इस संबंध में प्राधिकरण ने नोट किया कि ट्राई आईपीएलसी हॉफ सर्किट के लिए कोई सिंगल टैरिफ विनिर्दिष्ट नहीं कर रहा है बल्कि यह टैरिफ की अधिकतम सीमा दे रहा है। अधिकतम टैरिफ के निर्धारण में सेवा प्रदाता को अलग–अलग गंतव्यों/रूटों आदि के लिए अलग–अलग टैरिफ की पेशकश करने की पूरी स्वतंत्रता है, बशर्ते कि ऐसे टैरिफ अधिकतम टैरिफ से कम हों। चूंकि टैरिफ की अधिकतम सीमा में लागत की तुलना में काफी मार्जिन है, खासतौर पर जब हम इस प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान की लागत पर विचार करें। इससे सेवा प्रदाता को समग्र लागत को कवर करते हुए उपयुक्त टैरिफ पैकेज प्रदान करने की लोचशीलता रहती है। इसके अलावा, जैसा कि पहले नोट किया गया है वीएसएनएल

(VANL) ने पहले संस्थापित सापेक्ष रूप से मंहगे सर्किटों की लागत की पहले ही भरपाई कर ली है।

"अन्तरराष्ट्रीय रूप से आईपीएलसी के जरिए कीमतों का विनियमन बहुत ही विरल किया जाता है।"

61. प्राधिकरण ने बहुत से देशों में आईपीएलसी बाजार को शासित करने वाले विनियमों के संदर्भ में अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहारों की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा के परिणाम तालिकाबद्ध किए गए हैं और बहुत से देशों में आईपीएलसी सेक्टर को शासित करने वाले विनियामक संव्यवहार का ब्यौरा अनुबंध–क–परिशिष्ट 1 की **तालिका** 8 में दिया गया है। इस समीक्षा के अनुसार उन बाजारों में जिन्हें इस समय प्रतिस्पर्धी माना जाता है, किसी न किसी समय विभिन्न किस्म के विनियम लागू थे, जिनमें टैरिफ को विनियमित किया जाना भी शामिल है। अब भी आईपीएलसी के लिए कुछ प्रतिस्पर्धी बाजारों में प्रमुख ऑपरेटरों पर इस प्रकार के टैरिफ विनियम लागू हैं कि उन्हें विनियामक के पास टैरिफ दर्ज कराना अपेक्षित है। तत्पश्चात् उनकी विस्तृत जांच पड़ताल की जाती है तथा पूर्वानुमति दी जाती है। इन ऑपरेटरों द्वारा प्रस्ताव किए गए कीमतों से विनियामक के संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें लागू किया जाता है। प्राधिकरण से किए गए इन्कमबेंट के अनुरोध से भी यह स्पष्ट होता है कि वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान तथा यूरोपीय यूनियन के देशों में आईपीएलसी सेक्टर विनियमित है। वियतनाम के मामले में यह प्राइस बैंड/अधिकतम सीमा तथा विनियामक के पूर्व अनुमोदन के रूप में है। ताइवान के मामले में प्रमुख ऑपरेटरों के लिए कीमत/अधिकतम सीमा के रूप में विनियमन लागू है। सिंगापुर में प्रमुख आईपीएलसी प्रदाता को टैरिफ के संबंध में विनियामक की पूर्व अनुमति लेनी होती है। कुछ बाजारों में जहां इस समय विनियमन स्पष्टतः नहीं दिखाई देता है उन बाजारों में मौजूद परिस्थितियां भारतीय आईपीएलसी बाजार की परिस्थितियों से पूरी तरह से अलग हैं। प्रत्येक देश को यह निर्णय करना होता है कि किसी बाजार को विनियमित किया जाए या न किया जाए। भारत के मामले में आईपीएलसी विनियम लागू करने का पर्याप्त आधार है।

"अकेल वीएसएनएल वाणिज्यिक केबल के संकाय निर्णयों को नियंत्रित नहीं करता है।"

62. प्राधिकरण को भेजे गए अपने अनुरोध में वीएसएनएल ने कहा कि भारत में अधिकांश केबल लैंडिंग का स्वामित्व/नियंत्रण एक संकाय के हाथ में है, जो केबल की क्षमता अपग्रेड करने और उसके विस्तार का निर्णय लेता है। इस मामले में एक सदस्य की भूमिका बहुत सीमित होती है। वीएसएनएल ने कहा कि संकाय केबल के क्षमता विस्तार का कार्य बहुत की खर्चीला है और अलग–अलग सदस्यों को लोचशीलता प्रदान करते हुए संकाय द्वारा चालू पुनर्स्थापन के तथा ओ एण्ड ए के ठेकों के बारे में वार्ता (सौदा) किया जाता है।

63. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि वीएसएनएल के उपर्युक्त प्रतिवाद ये यह स्पष्ट होता है कि वीएसएनएल ने इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि जब कभी प्राधिकरण द्वारा कीमतें निर्धारित की जाए या टैरिफ आदेश जारी किए जाएं उन्हें इन्हें अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं है। वास्तव में वीएसएनएल ने प्राधिकरण से यह अनुरोध किया था कि वे प्राधिकरण की इच्छानुसार कीमतें कम करेंगे परन्तु वे प्राधिकरण द्वारा परामर्श–पत्र में प्रस्ताव किए गए अनुसार इन कीमतों में भारी गिरावट नहीं चाहते थे। वीएसएनएल के साथ अपनी बैठकों के दौरान भी इस बारे में उनसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया और वे इस बात से सहमत थे कि आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) की कीमतों में परिवर्तन करने की लोचशीलता उनके पास है।

64. प्राधिकरण का मत है कि टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्रक्रिया को कई बार बढ़ाया गया है ताकि आईपीएलसी प्रदाताओं द्वार बार–बार किए जाने वाले विभिन्न अनुरोधों को समाहित किया जा सके। यह इसका एक उदाहरण है कि एक ऐसे बाजार में, जहां प्रतिस्पर्धा की कमी है और जहां विनियामक कार्रवाई अपेक्षित है, वे आईपीएलसी की कीमतों में परिवर्तन करने के लिए अनिच्छुक हैं।

"वीएसएनएल के भारित औसत राजस्व वसूली E 1 टैरिफ से कम है।"

65. वीएसएलएल ने दावा किया है कि परामर्श–पत्र में प्रस्तावित टैरिफों से सभी क्षमताओं के लिए होने वाली भारित औसत राजस्व E 1 की कीमतों से कम होगा। अधिकतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्राधिकरण की पद्धति में इसे ध्यान में रखा गया है। प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि लेखा पृथक्करण के भाग के रूप में वीएसएनएल द्वारा सूचित लागत के लेखा परीक्षित आंकड़ों की अब विस्तृत गणना करने पर पता चलता है कि वीएसएनएल को सेवाएं प्रदान करने की लागत की तुलना में टैरिफ में अधिशेष प्राप्त होता है। वीएसएनएल के अनुरोध में यथा संभव ज्यादा लागत दिखाने तथा विनिर्दिष्ट टैरिफ की लागत पर ज्यादा मार्जिन प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। भारित औसत राजस्व की वसूली तथा इन्कमबेंट की औसत लागत की जांच करने पर तथा तीनों क्षमताओं के प्रोडक्ट–मिक्स अनुपात के संबंध में मार्केट के आंकड़ों के आधार पर आगे विश्लेषण करने पर यह सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित टैरिफ न केवल औसत लागत कवर करता है बल्कि इससे इन लागतों के लिए पर्याप्त बफर की व्यवस्था भी हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि ये टैरिफ अभी भी कुछ देशों में मौजूद टैरिफ से ज्यादा हैं, खासतौर पर उच्चतर क्षमताओं के लिए। प्राधिकरण की ठोस राय है कि आईपीएलसी के टैरिफ, जो कई प्रकार के सामाजिक तथा आर्थिक कार्यकलापों का महत्वपूर्ण साधन है, को पूरी तरह ऑपरेटरों के वाणिज्यिक विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है, खासतौर पर तब जब प्राधिकरण बाजार को प्रतिस्पर्धी नहीं मानता हो।

"उच्चतर लाइसेंस शुल्क से आईपीएलसी का टैरिफ बढ़ता है।"

66. वीएसएनएल (VSNL) ने कहा है कि आईपीएलसी की उच्चतर लागत का एक कारण लाइसेंस शुल्क का ज्यादा होना है (समायोजित सकल राजस्व का 15%), जैसा कि भारत में लागू होता है। अधिकांश देशों में राजस्व शुल्क इससे काफी कम है। इस संबंध में प्राधिकरण ने नोट किया कि वीएसएनएल का तर्क सही नहीं है क्योंकि लागत, 15% के लाइसेंस शुल्क को ध्यान में रखकर निकाली गई है। वास्तव में, यूनिफाइड लाइसेंस प्रणाली में प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि लाइसेंस शुल्क 6% हो और यदि लाइसेंस शुल्क बढ़ाई जाती है तो इससे आईपीएलसी सेवा प्रदाताओं के लिए मार्जिन और बढ़ेगा।

आईएलडीओएस के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण तदनुसार ही अधिकतम सीमा कम करेगा।

प्राधिकरण के टैरिफ आकलन को शेयर करना, वास्तविक टैरिफ मुहैया कराने के लिए समय मांगना और प्राधिकरण द्वारा यदि बाहरी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं तो उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क की अनुमति प्रदान करने देने का अनुरोध।

67. प्राधिकरण ने इन्कमबेंट के इस मुद्दे को नोट किया और देखा कि परामर्श–पत्र के जारी होने से पहले तथा उसके बाद में इन्कमबेंट ने ट्राई के साथ कई बैठकें की, इसलिए प्राधिकरण का मानना है कि प्राधिकरण द्वारा परामर्श–पत्र जारी किए जाने से पहले और परामर्श–पत्र जारी होने के बाद सूचना, आंकड़े, विचार तथा बाजार की गतिविधियों के बारे में अन्य अवधारणाओं, आदि को शेयर करने के लिए इन्कमबेंट को पर्याप्त अवसर दिया गया था। आईपीएलसी के कीमत निर्धारण के संबंध में जुलाई, 2003 से फरवरी, 2004 तक वीएसएनएल तथा ट्राई के बीच कई बैठकें हुई। परामर्श–पत्र जारी होने के बाद भी वीएसएनएल के अनुरोध पर ट्राई ने उनके परामर्शदाता अर्थात् बीसीजी को विचार–विमर्श की एक श्रृंखला का मौका दिया (8.10.04 से 27.10.04 के दौरान) जिसकी परिणति 16.2.05 को प्राधिकरण को रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण से हुआ। इन्कमबेंट भली भांति यह जानता है कि प्राधिकरण अधिकतम टैरिफ को वास्तविक कीमत में परिवर्तन कर निर्धारित करता है, न कि सूचीबद्ध कीमत के आधार पर क्योंकि अन्यथा कीमत में परिवर्तन का प्रभाव मौजूद रियायत में परिवर्तन (समाप्त कर) करने से काफी हद तक समाप्त हो जाता है। इसके बावजूद इन्कमबेंट तथा इसके विशेषज्ञों ने अन्त तक सूचीबद्ध कीमतों में कीमतों की तुलना प्रस्तुत की।

68. प्राधिकरण ने टैरिफ के आकलन के लिए भी वीएसएनएल के साथ कई बैठकें की, इसी कारण उन्होंने इस पद्धति को बदलने के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए। आईपीएलसी टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रस्तावों के प्रतिपादन में उनके द्वारा समय–समय पर उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखा गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस टैरिफ आदेश जारी करने की पृष्ठभूमि तथा परिस्थितियां, इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित आंकड़ों तथा टैरिफ निर्धारण

से संबद्ध सूचना/पद्धति का ब्यौरा दिया गया है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त बाहरी परामर्शदाताओं से इन्कमबेंट को विचार–विमर्श करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब तक प्राधिकरण ने ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई है जिसमें प्राधिकरण द्वारा लगाए गए बाहरी परामर्शदाता के साथ संपर्क का मौका दिया गया है। प्राधिकरण की राय में ऐसे अनुरोध स्वीकार करना उचित विनियामक कार्य भी नहीं है। प्राधिकरण की राय में यह परामर्श प्रक्रिया में बाधा डालने का एक प्रयास है, जिनकी वास्तव में शुरूआत अप्रैल, 2004 में हुई।

E 1 से कम क्षमता के लिए कीमतें

69. E 1 से नीचे की छोटी क्षमताओं के लिए आईपीएलसी क्षमताओं के लिए अलग से अधिकतम कीमत निर्धारित न करने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि छोटी क्षमताएं जो कुल उच्चस्तरीय बैंडविथ मांग का बहुत की कम भाग है, भविष्य में महत्वहीन हो जाएंगी। इन्कमबेंट की पिछले वर्ष की विभिन्न क्षमताओं की बिक्री के आंकड़ों से भी यह स्पष्ट है। अतः इस प्रकार की क्षमताओं को छोड़ दिया गया है।

भिन्न उपयोग के लिए कीमतें

70. परामर्श–पत्र में उठाया गया दूसरा मुद्दा विभिन्न उपयोगों के लिए अर्थात् वॉयस अथवा डाटा के लिए इस अधिकतम सीमा को लागू करने से संबंधित है। आर्थिक तथा लागत के संदर्भ में डाटा या वॉयस के लिए आईपीएलसी की व्यवस्था करने की लागत में बहुत कम अन्तर है। अतः सम्बद्ध आईपीएलसी टैरिफ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से संबंधित औचित्य में कोई अन्तर नहीं है। अधिकांश स्टेकहोल्डरों का मत था कि प्रस्तावित टैरिफ की अधिकतम सीमा समान होनी चाहिए, चाहे इसे वॉयस के लिए इस्तेमाल किया जाए या डाटा के लिए। उपयुक्त को देखते हुए प्राधिकरण ने आईपीएलसी ऑफ सर्किट के टैरिफ, चाहे उसका इस्तेमाल वॉयस के लिए हो या डाटा के लिए, समान रखने का निर्णय लिया है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसो0 ऑफ इंडिया ने अपने पत्र में कहा कि अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी की लागत का सारा भार आईपीएलसी पर डालना उचित नहीं है। इस संबंध में प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि आईपीएलसी के लिए लागत आधारित कीमत का आकलन करने के लिए 2003–04 के लिए पृथक लेखाओं, जिनकी आईपीएलसी

सेगमेंट के लिए लेखा परीक्षा की गई थी, को लिया गया। पृथक लेखाओं में अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी के बिजनेस के लिए इसी प्रकार के लागत के ब्यौरे अलग से उपलब्ध थे इसलिए सीओएआई का कथन सही नहीं है। वीएसएनएल द्वारा आईएलडी कॉलों के लिए आईपीएलसी का इस्तेमाल करने की स्थिति में वीएसएनएल को ऐसे उपयोग के लिए वही प्रभार लगाना चाहिए जो प्रभार दूसरों पर लागू होता है।

सैटेलाइट आईपीएलसी के लिए टैरिफ प्रविरिति

71. जैसा कि पद्धति में उल्लेख किया गया है सैटेलाइट आईपीएलसी से संबंधित लागत पर विचार नहीं किया गया है इसलिए सैटेलाइट आईपीएलसी के टैरिफ प्रविरिति रखी गई है।

हॉफ सर्किट आईपीएलसी के लिए मानक टैरिफ अनिवार्य करना।

72. आईपीएलसी सेवा के प्रावधान में दो तत्व शामिल हैं अर्थात् भारतीय छोर का एक हॉफ सर्किट तथा दूरस्थ छोर का दूसरा ऑफ सर्किट। आईपीएलसी के लिए ट्राई के विनियम/टैरिफ आदेश में आईपीएलसी के उस नजदीकी छोर वाला भाग ही शामिल किया जा सकता है, जिसकी भारत के किसी लाइसेंसधारी आईएलडीओ द्वारा पेशकश की जाती है। भारत में आईएलडीओएस, विदेशी वाहक के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थाएं करके आईपीएलसी की पूर्ण सर्किट की सेवाएं प्रदान करते हैं, परन्तु ट्राई का टैरिफ आदेश भारत से सम्बद्ध नजदीकी छोर के हॉफ सर्किटों पर ही लागू होता है। पूर्ण सर्किट की सेवा और ग्राहकों के लिए उस सेवा के टैरिफ की पेशकश करके इस टैरिफ आदेश को, जिसमें केवल हॉफ सर्किट के टैरिफ का अधिदेश है, उलझाया जा सकता है।

73. अतः प्राधिकरण ने एक ऐसे मानक टैरिफ पैकेज का अधिदेश दिया है जिसमें प्रत्येक कोटि तथा गंतव्य, जिसके लिए आईएलडीओएस द्वारा पूर्ण सर्किट सेवाओं की पेशकश की जाती है, के लिए हॉफ सर्किट की अधिकतम टैरिफ की पेशकश की जाएगी। इससे प्राधिकरण, सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ आदेश के अनुपालन पर नजर रख सकता है। बहरहाल, आईएलडीओएस, बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक पैकेज की पेशकश भी कर सकते हैं।

निष्कर्ष

74. इस संदर्भ में प्राधिकरण, टैरिफ की कमी के परिणामस्वरूप भारत में मोबाइल टेलीफोनी के विकास को ध्यान में रखता है। इसी प्रकार आईपीएलसी के लीज प्रभारों में कमी होने से इसका भी भारी विकास होगा। इस तर्क का समर्थन स्वतंत्र अध्ययनों द्वारा उल्लिखित प्रमाणों के द्वारा भी हुआ है जिसमें कहा गया है कि भारत में फिक्सड डाटा सेवाओं में तेजी से वृद्धि होने का पूर्वानुमान है, जो 2004–2008 तक प्रतिवर्ष औसतन कम से कम 20% होगा, अर्थात् यह विकास चीन से ज्यादा रहेगी। भारत में विकास का अनुभव यह है कि कम कीमत होने से वॉयस टेलीफोनी के सब्सक्राइबरों में भारी वृद्धि हुई और ऐसी आशा करना उचित ही होगा कि यही कहानी ब्राडबैंड/इंटरनेट और दूसरी डाटा सेवाओं, जो इन्टरनेशनल बैंडविथ पर पूरी तरह निर्भर हैं, में भी दोहराई जाएगी। अतः आईपीएलसी के लिए लागत आधारित टैरिफ का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है, परन्तु प्राधिकरण द्वारा अधिदेशित कम कीमतों के कारण मांग में वृद्धि से ऑपरेटरों की क्षमता का उच्चतर उपयोग होगा, जिसका गौण प्रभाव कीमत के स्तर को नीचे लाएगा। व्याख्यात्मक ज्ञापन में कई ऐसे अन्य कारण दिए हैं, जिनकी वजह से आईपीएलसी के टैरिफ की अधिकतम सीमा के संबंध में प्राधिकरण का हस्तक्षेप जरूरी है।

उपर्युक्त के आधार पर निम्नानुसार आईपीएलसी टैरिफ विनिर्दिष्ट किए गए हैं:

क्षमता	**कीमत (लाख रुपयों में)**
ई 1	13
डीएस 3	104
एसटीएम–1	299

75. प्राधिकरण एक वर्ष के भीतर आईपीएलसी सेगमेंट में विकास से संबंधित स्थिति की समीक्षा करेगा। अलग से भी प्राधिकरण केबल लैंडिंग स्टेशनों के लिए लागत आधारित एक्सेस कीमत, से संबंधित मुद्दों और बोटलनेक सुविधा के भाग के रूप में केबल लैंडिंग स्टेशन से उत्पन्न मुद्दों तथा आईपीएलसी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा का वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर आवश्यक परामर्श–पत्र जारी करेगा।

अनुबंध–क का परिशिष्ट–I

तालिका सं0 1 : भारत में आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) लीज किराए–वीएसएनएल

(संगत अवधि के दौरान मौजूद विनियम दर लागू की गई है)

वर्ष	वार्षिक लीज किराया					
	ई1 (2 एमबीपीएस)		डीएस–3 (45 एमबीपीएस)		एसटीएम–1 (155 एमबीपीएस)	
	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर	लाख रुपए में	अमेरिकी डॉलर
2002*	26	54,629	471	990,126	1365	2,867,647
2003#	30.8	67,102	471	1,026,797	1365	2,973,856
1.1.04#	23.7	52,202	445	980,176	1235	2,720,264
1.4.04#	21.3	48,519	401	913,439	1112	2,533,029
2005#	20.2	45,909	361	820,454	1000	2,272,727

नोटः प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है, क्योंकि यह विभिन्न मानदण्डों पर आधारित होता है।

* आईपीएलसी सेवाओं के टैरिफ, चाहे गंतव्य जो भी हो।

\# रि–स्टोरेबल श्रेणी तथा भारत से दूरस्थ गंतव्य के लिए लागू टैरिफ

तालिका सं0 2–वर्तमान आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) टैरिफ–भारती इन्फोटेल

क्षमता	**वार्षिक लीज किराया**	
	लाख रुपए में	**अमेरिकी डॉलर**
ई 1	9.81	22295
डीएस 3	175.50	398864
एसटीएम–1	418.50	951136

नोट
1. भारती इन्फोटेल की आईपीएलसी सेवाएं केवल नॉन–रिस्टोरेबल श्रेणी के लिए है (यथा–संसूचित)
2. उक्त टैरिफ भारत से दूरस्थ गंतव्य के लिए है।
3. प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है क्योंकि यह विभिन्न मानदण्डों पर निर्भर होता है।
4. विनिमय दर : 1 अमेरिकी डॉलर = 44रु0

तालिका 3–वर्तमान आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) टैरिफ–रिलांयस इन्फोकॉम

क्षमता	**वार्षिक लीज किराया**	
	लाख रुपए में	**अमेरिकी डॉलर**
ई 1	(पूर्ण सर्किट टैरिफ 69.9 लाख रूपए)	(पूर्ण सर्किट टैरिफ 159,000)
डीएस 3	427	971,500
एसटीएम–1	1238	2,815,000

<u>नोट</u> 1. उपर्युक्त टैरिफ सभी गंतव्यों पर लागू है।

2. प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है।

वीएसएनएल, भारती तथा रिलायंस इन्फोटेल की रियायत संरचना इस प्रकार है।

(1) बीएसएलएन

प्रस्तावित रियायत सशर्त है जिसमें बड़ी क्षमता/सर्किट को खरीदने की वचनबद्धता है और यह वचनबद्धता है कि लम्बी अवधि (वर्षों के हिसाब से) के लिए खरीदा जाए। भारत में E 1 के मामले में वाल्यूम (सर्किटों) और वाल्यूम (बैंडविथ) के लेखे में रियायत कुल मिलाकर सूचीबद्ध कीमत के 15% तक है। 3 वर्ष की लम्बी अवधि की वचनबद्धता के लिए10% का अतिरिक्त रियायत प्राप्त होता है। DS-3 तथा STM-1 की दरों के मामले में रियायत की अधिकतम दर क्रमशः 20% और 15% होती है। इसमें लम्बी अवधि की वचनबद्धता से मिलने वाली रियायत शामिल नहीं है (3 वर्ष के लिए 10%)

(II) भारती

रियायत की पेशकश मामला–दर–मामला आधार पर की जाती है। रियायत योजनाओं में पात्रता के मानदण्ड लम्बी अवधि की बिजनेस वचनबद्धता तथा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्भर करते हैं। रियायत की दरें विनिर्दिष्ट नहीं है और इनका विकल्प खुला है।

(III) रिलायंस

रियायत की अधिकतम दर 40% संसूचित की गई है और यह निम्नलिखित मानदंडों पर निर्भर करता है :

- ग्राहक से कुल राजस्व
- आदेश तथा संविदा अवधि दोहराना
- विशिष्ट स्थान पर क्षमता उपयोग
- वांछित शर्तों का पालन
- कैरियर पार्टनर का ग्लोबल ग्राहक
- मल्टीपल ग्लोबल रूट डायवर्सिटी

तालिका 4

भारत में वर्तमान सूचीबद्ध आईपीएलसी की कीमत (हॉफ सर्किट) और आईपीएलसी के लिए निर्धारित अधिकतम टैरिफ की तुलना

क्षमता	वार्षिक लीज किराया		कटौती की सीमा
	वर्तमान सूचीबद्ध कीमत	निर्धारित अधिकतम टैरिफ	
	लाख रूपए में	लाख रूपए में	
ई 1	20.2	**13**	35%
डीएस 3	361	**104**	71%
एसटीएम–1	1000	**299**	70%

नोट 1. उक्त टैरिफ भारत से दूरस्थ गंतव्य के लिए है।

2. प्रदान की गई रियायत को हिसाब में नहीं लिया गया है क्योंकि यह विभिन्न मानदण्डों पर निर्भर होता है।

3. वीएसएनएल के वर्तमान सूचीबद्ध टैरिफ को उक्त तालिका में सूचीबद्ध कीमत माना गया है।

तालिका 5– आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) ई1 कीमत की अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	वर्तमान कीमत (अमेरिकी डॉलर हजारों में)
जापान–यूएसए	23
दक्षिण कोरिया–यूएसए	23
हांगकांग–यूएसए	24
सिंगापुर–यूएसए	33
भारत–यूएसए*	39

तालिका 6– आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) डीएस–3 कीमत की अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	वर्तमान कीमत (अमेरिकी डॉलर हजारों में)
जापान–यूएसए	99
दक्षिण कोरिया–यूएसए	102
हांगकांग–यूएसए	124
सिंगापुर–यूएसए	174
भारत–यूएसए*	656

तालिका 7– आईपीएलसी (हॉफ सर्किट) एसटीएम–3 कीमत की अंतरराष्ट्रीय तुलना

देश	वर्तमान कीमत (अमेरिकी डॉलर हजारों में)
जापान–यूएसए	191
दक्षिण कोरिया–यूएसए	229
हांगकांग–यूएसए	269
सिंगापुर–यूएसए**	346
भारत–यूएसए*	1931

*दूरस्थ गंतव्यों के लिए लागू वीएसएनएल के आईपीएलसी टैरिफ से संबंधित है और वाल्यूम पर अधिकतम रियायत को हिसाब में लिया गया है।

** DS-3 तथा STM-3 के टैरिफ कम होने के कारण सिंगापुर के E-1 टैरिफ ज्यादा हैं ।

नोटः अन्य देशों में भी DS-3 तथा STM-3 के कीमत मल्टीपल भारत में बहुत कम हैं।

स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय डाटा के लिए अरनेस्ट एंड यंग/टेलीजियोग्राफी ।

तालिका–8 अन्तरराष्ट्रीय रूप से आईपीएलसी प्रोडक्ट की विनियामक तथा प्रतिस्पर्धा की स्थिति इस प्रकार है :

देश	विनियम
आस्ट्रेलिया	1992 से 2001 के बीच राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय लीज लाइन CPI-X% कीमत नियंत्रण के अंतर्गत थे। जब इन्टरनेशनल लीज्ड लाइन के बाजार को प्रतिस्पर्धी समझा गया तब बाद में इसे हटा दिया गया।
चीन	सभी लीज लाइनों की दरें सरकार द्वारा निर्धारित हैं। आगे कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।
हांगकांग	अप्रैल, 2001 में फिक्सड टेलीकॉम नेटवर्क सेवाएं मुहैया कराने के लिए कैरियर लाइसेंस प्रणाली लागू की गई और प्रमुख ऑपरेटरों के लिए अधिकतम सीमा का प्रावधान किया गया। REACH एकमात्र प्रमुख ऑपरेटर था। मार्च, 2002 में ओएफटीए ने घोषित किया कि REACH प्रमुख ऑपरेटरा नहीं रह गया है इसलिए अधिकतम कीमत हटा दी गई है।
आयरलैंड	कामरेग, इस समय आईपीएलसी के बाजार के संदर्भ के परामर्श प्रक्रिया का काम कर रहा है। कामरेग का इस समय विश्वास है कि आईपीएलसी के लिए घरेलू बाजार प्रतिस्पर्धी है और EIRCOM के सभी दायित्वों, जिसमें इस समय लागत, तथा प्रतिस्पर्धियों को गैर–भेदभावपूर्ण अभिगम्यता प्रदान करना भी शामिल है, को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।
जापान	जापान में ऑपरेटरों को टाइप I तथा टाइप II के रूप में परिभाषित किया गया है। टाइप–I के ऑपरेटरों पर अधिकतम कीमत निर्धारण की व्यवस्था लागू है और टैरिफ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लागू करने से पूर्व विनियामक से अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है। सभी विनियमन 2001 में समाप्त कर दिए गए क्योंकि विनियामक ने यह समझा कि DPLCs तथा IPLCs के लिए बाजार अब प्रतिस्पर्धी हो गया है।

सिंगापुर	सिंगापुर में प्रमुख लाइसेंसधारी को विनियामक के पास अनुमोदन के लिए टैरिफ दायर करने होते हैं। सिंगेटेल, आईपीएलसी का प्रमुख प्रदाता माना जाता है और इसलिए उसे आईडीए के पास सभी टैरिफ संशोधन दायर करने होते हैं और आईडीए को यह आकलित करना होता है कि क्या ये टैरिफ नियमानुकूल हैं और यह जांच करनी होती है कि क्या ये भेदभावपूर्ण तो नहीं है और क्या ये लागत आधारित हैं। इसके अलावा, 2001 में आईडीए ने व्यवस्था दी कि वैकल्पिक ऑपरेटर अपने इक्यूपमेंट सिंगटेल के लैंडिंग स्टेशन पर रख सकते हैं। अप्रैल 2002 में इसमें संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि सिंगटेल को वैकल्पिक ऑपरेटरों को कनेक्शन मुहैया कराना जरूरी है, आईडीए का दृष्टिकोण अन्तरसंयोजन अधिकार लागू करना तथा बाजार को फुटकर टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देना है।
द0 कोरिया	अन्तरराष्ट्रीय लीज्ड लाइन मार्केट में 14 लाइसेंसधारी हैं – आईपीएलसी के लिए बाजार को प्रतिस्पर्धी माना जाता है।
यूनाइटेड किंगडम	बाजार को प्रतिस्पर्धी समझा जाता है – कोई विनियमन नहीं
संयुक्त राज्य अमेरिका	बाजार को प्रतिस्पर्धी माना जाता है – कोई विनियमन नहीं

स्रोतः एर्नास्ट एण्ड यंग